ASSOCHAM
INDIA

हरियाणा स्वर्ण उत्सव

बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा

HARYANA KISAN AYOG • हरियाणा किसान आयोग • 2010 •

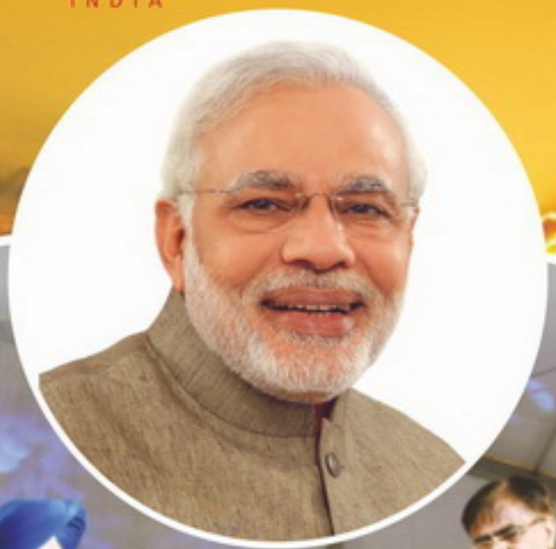

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

• सफल व्यक्तियों के माध्यम से प्रेरणा • परिनगरीय खेती
• खेत से सीधा उपभोक्ता तक • इलेक्ट्रॉनिक फार्म ट्रेडिंग • जैविक खेती • ए2 दूध : स्वास्थ्यवर्धक दूध

18–20 मार्च, 2017 सूरजकुण्ड, फरीदाबाद, हरियाणा

कार्यक्रम रिपोर्ट

माननीय मुख्यमंत्री द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2017 में प्रेस को सम्बोधित करते हुए

हरियाणा स्वर्ण उत्सव
बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

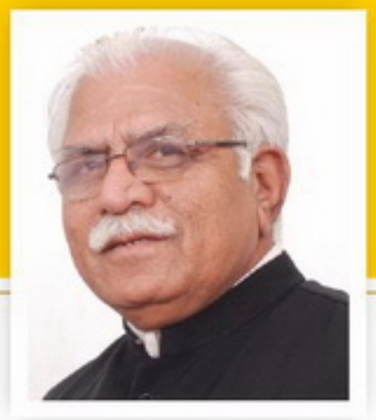

श्री मनोहर लाल
माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा

हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कार्य बल के 51 प्रतिशत को रोजगार देता है और इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 14.5 प्रतिशत योगदान देता है। राज्य ने हरी, सफेद, नीली और पीली क्रांतियो को देखा है देश के केवल 1.4 प्रतिशत क्षेत्र के होने के बावजूद खाद्य अनाज के केंद्रीय पूल में 15.6 प्रतिशत का योगदान देता है। नीति बनाने और नियोजन में उपलब्धियों के कारण, हरियाणा के किसानों की कड़ी मेहनत से, प्रौद्योगिकी जनन और प्रसार से यह संभव हो पाया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि हमेशा राज्य अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक होगी।

किसानों की आय संतोषजनक रूप से नही बढ़ रही है। इसने भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान खींचा है। उन्होंने योजनाकारों, वैज्ञानिकों और वित्तीय संस्थानों को वर्ष 2022 तक अपनी आय को दोगुना करने में मदद करने के लिए रणनीतियों और तकनीक के साथ आने के लिए एक मजबूत अपील की है। हमने हरियाणा में इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं। यही कारण है कि हमने कृषि और किसानों के कल्याण विभाग के रूप में कृषि विभाग को नया नाम दिया है।

इससे पहले राज्य का केन्द्र बिन्दु उपज बढ़ाने पर था, लेकिन अब स्थिरता, वृद्धि और किसान की आय प्रमुख केन्द्र बिंदु है। राज्य सरकार कम होते प्राकृतिक संसाधनों का श्रेष्ठ रूप से प्रयोग करने और बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईसीटी और खेतों के नवप्रवर्तन, मंडियों के आधुनिकीकरण और भण्डारण सुविधा, प्रत्यक्ष विपणन और फसलों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा देना, फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन व प्रसंस्करण और मूल्य वृद्धि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग की पहल सराहनीय है। इन प्रयासों से निश्चित तौर पर किसानों की आय में उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप वृद्धि होने में मदद मिलेगी।

मैं, श्री ओम प्रकाश धनखड़, कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री और उनकी टीम को हरियाणा कृषि में एक आदर्श बदलाव लाने के सफल प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। कृषि विभाग ने कृषि विस्तार और सूचना के प्रसार को रूपांतरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि किसानों को नवीनतम नवाचार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य उत्पादन से सप्लाई और बाजार उन्मुखीकरण से खेती के पूरे दृष्टिकोण को बदलना है। दो बेहद सफल कृषि–नेतृत्व शिखर सम्मेलन एक गुरूग्राम में और दूसरा फरीदाबाद में आयोजित होने से हरियाणा कृषि में बदलाव लाने में काफी सहायक होगा।

मुझे यकीन है, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि को एक प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्र बनाने और राज्य के युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी, फायदेमंद और आकर्षक बनाने के लिए अपने दृष्टिकोण में सुधार करता रहेगा।

मनोहर लाल

श्री मनोहर लाल
माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा

Sh. Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister, India
Sh. Rajnath Singh
Hon'ble Union Minister Home Affairs
Suraj Ku

ASSOCHAM

2nd AGRI LEADERS
SUMMIT 2017

Inauguration of Summit
18 March 2017
2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017

संदेश

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

श्री ओम प्रकाश धनखड़

मानानीय कृषि, एवं किसान कल्याण, सिंचाई, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य तथा विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017 ने अपने नवप्रवर्तक अग्रणी किसानों और कृषि के विविधीकरण के लिए प्रभावी कृषकों को ''रत्न'' के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया। मुझे खेती रत्न पुरस्कार प्रदान करने में अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ क्योंकि हमारे कृषको ने न केवल प्रदेश में बल्कि पूर देश में हरियाणा का नाम ऊँचा कर दिया। हमारे विभिन्न ''रत्न'' है–जैविक खेती रत्न श्री राजेश खेरी, फूल खेती रत्न सुश्री शिवानी महेश्वरी, औषिधि खेती रत्न श्री बिशन पाल सिंह राणा, सब्जी खेती रत्न श्री सिलक राम धनखड़, शहद रत्न श्री राजेन्द्र कुमार सहारन, मशरूम रत्न श्री अनिल कुमार सैनी, मत्सय रत्न श्री जय पाल सिंह एंव कुक्कुट रत्न श्री जसबीर देसवाल। ये वो रत्न है जो वास्तविक रूप से अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत् है और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन के लिए राजदूत का दायित्त्व भी निभाएंगें जोकि राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मैं माननीय केन्द्र मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं चौ0 बीरेन्द्र सिंह और केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री एस0एस0 आहलूवालिया, श्री पुरूषोत्तम रूपाला एंव श्री कृष्ण पाल को इस शिखर सम्मेलन में उनकी सुखद उपस्थिति और अनुभवों को सांझा करने के लिए ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मोर्चा श्री विरेन्द्र सिंह मस्त, श्री लक्ष्मी नारायण यादव (एम0पी0), श्री बृज मोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ एंव श्री गौरी शंकर, कृषि मंत्री मध्यप्रदेश का आभारी हूं जिन्होनें इस सम्मेलन की सराहना की और कृषि क्षेत्र में आगामी तकनीकि विकास के लिए किसानों को उजागर करने हेतु प्रोत्साहित किया।

शिखर सम्मेलन में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सौलंकी और माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति से सम्मेलन को प्रोत्साहन मिला। उन्होनें किसानों और साथ ही आयोजको को प्रेरित किया और ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से करने की इच्छा रखी। श्री कंवर पाल सभापति, श्रीमति संतोष यादव, उप सभापति, श्री सुभाष बराला राज्य अध्यक्ष बीजेपी, हरियाणा के माननीय मंत्रीगण– श्री राम बिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, श्री विपुल गोयल, श्री मनीष ग्रोवर, श्रीमति सीमा त्रिखा एवं राज्य के कई सांसदों और विधायको ने भी इस सम्मेलन में किसानों को सम्बोधित किया और प्रेरित किया।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस शिखर सम्मेलन को कई दूतावासों के आयुक्त सहित विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयासो की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जा सकता है। श्री देवेन्द्र चौधरी, डॉ0 आन्नद कृष्णन, डॉ0 राशा उमर, श्री अर्ल रतारी, श्री विनोद पटेल, श्री करन सीकरी एंव श्री मखीजा ने भी किसानों के साथ बातचीत की और कार्यक्रम का समर्थन किया। विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से शिखर सम्मेलन की सफलता परिलक्षित होती है। आई0सी0ए0आर0 और एस0ए0यू0 के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने तकनीकि सहायता प्रदान की और शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न सेमिनारों को संबोधित करते हुए किसानों के साथ गहन चर्चा की। वास्तव में उन्होनें किसानों के साथ गतिविधियों की जीवन रेखा प्रदान की।

मैं पूरी तरह से समझता हूं कि तकनीकी नवप्रवर्तन ही राज्य की खेती में भविष्य की सफलता की कुंजी है। सूरजकुंड में ''द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन'' के दौरान, मैं योजनाओं, नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और पशु/डेरी प्रबंधन के बारे में जानने के लिए ग्रामीण युवाओं और किसानों की बढती दिलचस्पी को देखकर हैरान हुआ और अहसास हुआ कि यह एक अविश्सनीय उपलब्धि है। हरियाणा सरकार परिनगरीय कृषि को बढावा देने मे सक्षम है। युवाओं को राज्य कृषि को एक तकनीक संचालित व्यवसाय बनाने में नेतृत्व करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के युवा ए2 दूध, बासमती चावल, मौज़रेला पनीर, मशरूम, बेबी मकई, स्ट्रॉबेरी, शहद इत्यादि जैसी विशिष्ठ उत्पाद एंवम् उभरते सम्भावित विकल्पों की मांग को पूरा करने के लिए इच्छुक है। राष्ट्रीय राजधानी के आस–पास के क्षेत्र में होने के कारण हरियाणा में जैविक कृषि उत्पादों के लिए परिनगरीय कृषि के विकास में विशेष रूप से लाभ की गुंजाईश है। युवा भी कृषि को एक लाभदायक उद्यम में बदलने की क्षमता रखते है। उद्यमियता समृद्धि की कुंजी है और कृषि में सफलता के लिए भी सही है।

शिखर सम्मेलन की एक और आकृषक विशेषता थी ''पशु मेला''। यह हरियाणा के पशुधन का प्रदर्शन था। मैं नहीं सोचता की आप कभी भी किसी जगह पर 140 करोड के मुर्राह भैंसों को देख सकते है। मुर्राह वास्तव में हरियाणा का काला सोना है इसकी आनुवंशिक मूल्य के लिए विदेशों में भी मांग है।

मैं, हरियाणा के स्वर्ण जंयती समारोह के दौरान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों सहित आयोजकों को बधाई देता हूं। कार्यक्रम की सफलता के लिए किसान संगठनों और मीडिया कर्मियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं किसानों के लिए विभिन्न अच्छी गतिविधियों को पूरा करने और इस प्रकाशन के माध्यम से सम्मेलन का महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा किसान आयोग की सराहना करता हूं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़
मानानीय कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य
तथा विकास एवं पंचायत मंत्राी, हरियाणा

हरियाणा स्वर्ण उत्सव
1 नवम्बर, 2016-31 अक्टूबर, 2017

बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

संदेश

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

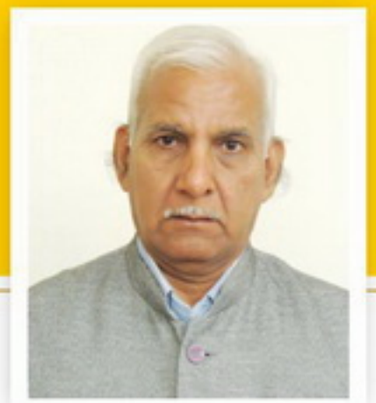

डा॰ रमेश कुमार यादव
अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग

'कृषि से कृषि व्यापार – ग्रामीण किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाना' के नारे के साथ 18–20 मार्च 2017 को सूरजकुण्ड, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन, 2017 के दो स्पष्ट उद्देश्य थे : हरियाणा को परिनगरीय खेती/बागवानी/सम्बद्ध गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में आगे बढ़ाना तथा कृषि व्यापार और विपणन नेतृत्व पर ध्यान केन्द्रित करना। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों जैसे किसानों की आमदनी दुगुनी करना, जलवायु के प्रति अनुकूल कृषि, सूक्ष्म सिंचाई/मृदा का स्वास्थ्य, जैविक खेती, जोखिम प्रबंध, ए2 दूध का उत्पादन/डेरी पालन, जल–जंतुपालन, कृषि वानिकी, कृषि उत्पादों का विपणन और कृषि उद्योगों आदि पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इस सम्मेलन से हरियाणा कृषि में वृद्धि की जो व्यापक और असीमित क्षमता है उसका लाभ उठाने के उद्देश्य की पूर्ति हुई जिससे राज्य में त्वरित, समग्र और टिकाऊ वृद्धि होना संभव है। इसके परिणामस्वरूप किसानों, खेती से जुड़े कर्मियों तथा उनके परिवारों की आर्थिक दशा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन से किसानों को सम्मानित करने, उन्हें पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। इस वृहत आयोजन में एक लाख से अधिक किसानों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों तथा नीतिकारों ने भाग लिया और उनमें इस मंच पर दर्शायी गई नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में बहुत उत्साह नजर आया।

हमारे कुछ कृषि नेताओं ने फार्म संबंधी नई–नई खोजों व खेती में विविधीकरण के संदर्भ में स्वयं को सिद्ध किया है और उन्हें 'खेती रत्न' से सम्मानित किया गया जो कि राज्य के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और वे खेती संबंधी नई–नई खोजों के बारे में उनमें जो प्रतिभा छुपी है, उसे उजागर करने में समर्थ होंगे।

मुझे इस तथ्य ने बहुत प्रभावित किया कि किसान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बागवानी, जैविक खेती, उन्हें मंडियों के साथ जोड़ना, प्रसस्करण व भंडारण, डेरी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए नए विचारों तथा नवोन्मेषों से सम्पन्न थे और उन्होंने कई उपयोगी खोजें व विचार प्रस्तुत किए। यह देखना हर्ष का विषय था कि किसानों ने अपने उत्पादों की 'ब्रांडिंग' शुरू कर दी है। इससे किसानों की गुणवत्ता, बाजार संबंधी मांग व बौद्धिक सम्पदा संबंधी मुद्दों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का पता चलता है। ऐसे प्रदेशों से यह बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि कृषि को 'प्रौद्योगिकी संचालित' बनाया जाना आवश्यक है और इसके लिए किसानों को फसलों की ऐसी किस्में विकसित करनी होंगी जो जैविक खेती, जल उपयोग की दक्षता और पोषणिक उपयोग की दृष्टि से अनुकूल हों। डेयरी क्षेत्र में गायों की देशी नस्लों को प्राथमिकता के साथ पंचगव्य उत्पादों पर केन्द्रित हों अनुसंधान एवं विकास के द्वारा भी किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।

कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017 कृषि को ग्रामीण युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक व लाभकारी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। सरकार ने 'कृषि में युवाओं के सशक्तीकरण' पर बल दिया है जिससे कृषि वृद्धि में तेजी लाने और इसके साथ–साथ फार्म व फार्म से इतर, दोनों प्रकार के उद्यमों से अधिक आमदनी लेने में बहुत मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार के प्रयास निश्चित रूप से ऐसा बुनियादी ढांचा व वातावरण निर्माण करने की दिशा में है जिससे कृषि व्यवसाय व इत्र उत्पाद की ओर युवाओं का आकर्षण बढ़ना स्वभाविक है।

डा॰ रमेश कुमार यादव
अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

डॉ. अभिलक्ष लिखी
प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2017 सूरजकुण्ड, फरीदाबाद के आयोजन को सफल बनाने मे विभिन्न विभागो (कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, परिवहन विभाग तथा मत्सय विभाग) बोर्ड एंव निगमो (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हैफेड, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा भूमि पुनर्मूल्यांकन एंव विकास निगम, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, हरियाणा किसान आयोग) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी का धन्यावाद करता हू। इस सम्मेलन मे किसानों तथा स्टोकहोल्डरों की भागीदारी अत्यधिक उत्साह वर्धक थी।

सभी जिलों के कृषि, बागवानी तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों ने इस सम्मेलन मे किसान भाइयों को अधिक संख्या में एकत्रित कर उन्हे सुविधा व सुरक्षा के साथ सम्मेलन मे लाने मे जो भूमिका निभाई, वो प्रशंसनीय है।

इस द्वितीय कृषि शिखर सम्मेलन में किसानों ने विशेष रूप में पशु प्रदर्शनी, बेबी/स्वीट कॉन उत्पादन, डेरी पालन, कुक्कुट विकास, खुम्बी की खेती, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन, हाई टेक बागवानी आदि की प्रदर्शनियों मे बढचढ़ कर हिस्सा लिया। इस सम्मेलन मे तीन दिन तक विभिन्न विषय पर किसान भाईयों के लिए सेमिनारो का आयोजन किया। जिसके द्वारा किसानो को नई–नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ।

इस सन्दर्भ मे कृषि तथा बागवानी विभाग, हरियाणा किसान भाईयो से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वचनबद्व और प्रयासरत है। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य शकिसानो की आय को 2022 तक दुगना करनेश के लिए, विभागो की योजनाओ के माध्यम से प्रबन्धकीय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी भी पूर्णतय तत्पर है।

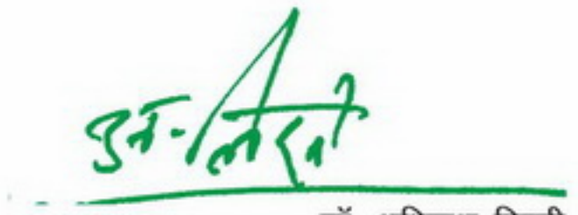

डॉ. अभिलक्ष लिखी
प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर
सम्मेलन-2017

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पेज
1.	भूमिका	01
2.	विशाल आयोजन – भव्य संगम	02
3.	समापन सत्र	07
4.	खेती रत्न	09
5.	विदेशी भागेदारी	10
6.	पशु प्रदर्शनी	11
7.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा – मुख्य उपलब्धियां	13
8.	प्रदर्शनी	15
9.	बागवानी विभाग, हरियाणा – मुख्य उपलब्धियां	17
10.	समझौता ज्ञापन (एमओयू)	19
11.	सेमिनार : विषय – ए2 दूध : स्वस्थ दूध	
	➢ दुग्धोत्पादन में क्रांति	21
	➢ गोपशु तथा जैविक खेती : मूलभूत तथ्यों पर लौटना	22
12.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा – मुख्य उपलब्धियां	23
13.	सेमिनार : विषय – ए2 दूध : स्वस्थ दूध	
	➢ पशुपालन एवं डेयरी में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रगतियां	25
14.	सेमिनार : विषय – परिनगरीय खेती – उभरता हुआ अवसर	
	➢ किसानों की आय दुगुनी करना	27
15.	हरियाणा किसान आयोग – मुख्य उपलब्धियां	29
16.	सेमिनार : विषय – परिनगरीय खेती – उभरता हुआ अवसर	
	➢ हरियाणा का भूदृश्य परिवर्तित करने के लिए बागवानी	31
	➢ किसानों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कृषि में प्राथमिकीकरण	33
18.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड – मुख्य उपलब्धियां	35
19.	सेमिनार : विषय – परिनगरीय खेती – उभरता हुआ अवसर	
	➢ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	37
	➢ परिनगरीय खेती	39
	➢ नीली क्रांति का विस्तार	41
20.	मछली पालन विभाग – मुख्य उपलब्धियां	43
21.	सेमिनार : विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार	
	➢ जल–संसाधनों का प्रबंधन	45
	➢ कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	46
	➢ टिकाऊ फसलोत्पादन के लिए संरक्षण कृषि– जलवायु अनुकूल कृषि और जोखिम प्रबंधन	47
22.	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हेफेड) – मुख्य उपलब्धियां	49
21.	सेमिनार : विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार	
	➢ सीधी बिक्री और इलेक्ट्रॉनिक बाजार	51
	➢ कृषि प्रचालन तंत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण – हरियाणा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र	53
24.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन – मुख्य उपलब्धियां	55
25.	भावी दिशा	57
26.	द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में बी2जी/जी2जी परिचर्चाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची	59
27.	हरियाणा सरकार की पहल – किसानों से सीधा संवाद	61
28.	सांस्कृतिक गतिविधियां	62
29.	सम्मेलन समाचार	63

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

भूमिका

भारत के प्रधानमंत्री देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने पर लगातार बल दे रहे हैं। तदनुसार हरियाणा सरकार ने खेत से होने वाली आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फार्म तथा फार्म से जुड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा अनुकूल बनाने व नीति हस्तक्षेप संबंधी कार्यक्रमों को अपनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। राज्य सरकार ऐसी कारगर तथा समयानुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित व संवेदनशील करने का निरंतर प्रयास कर रही है जिससे उन्हें घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा 18–20 मार्च, 2017 को सूरजकुण्ड में 'द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017' का आयोजन किसानों को नवीनतम तकनीकों व सूचना से सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक बड़ा प्रयास था।

इस सम्मेलन में मुख्य ध्यान इन विषयों पर दिया गया :

(i) उपलब्धियों के माध्यम से प्रेरणा

(ii) परिनगरीय खेती

(iii) फार्म से सीधे उपभोक्ता तक पहुंच

(iv) इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार

(v) जैविक खेती

(vi) ए2 दुग्धोत्पादन

मुख्य उद्देश्य तथा विषयों को ध्यान में रखते हुए कारगर तथा उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों, सफल किसानों के कार्य तथा विभिन्न नस्लों के श्रेष्ठ पशुओं की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त 16 मुख्य मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किया गया। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं डेरी; बागवानी; मात्स्यिकी विभागों व अन्य सम्बद्ध विभागों; हरियाणा किसान आयोग; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (एलयूवीएएस), बागवानी विश्वविद्यालय, पीएसयू, गौशालाओं, प्रगतिशील किसानों, उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्तकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों व बड़ी संख्या में किसानों आदि ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

विशाल आयोजन – भव्य संगम

दिनांक 18–20 मार्च, 2017 को 'द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन, 2017' के अंतर्गत विशाल कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये शानदार प्रदर्शन थे जिनमें बड़ी संख्या में किसानों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। दिनांक 18.03.2017 को श्री राज नाथ सिंह, भारत के माननीय गृह मंत्री, मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व हरियाणा सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री ओ.पी. धनखड़ ने मुख्य अतिथि श्री राज नाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार; श्री एस. एस. अहलुवालिया, कृषि एवं संसदीय मामले राज्य मंत्री, भारत सरकार तथा अनेक राज्य मंत्रियों व मंच पर आसीन अन्य महानुभावों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में श्री ओ.पी. धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मंडियों की आवश्यकता के अनुसार हरियाणा को कृषि राज्य के रूप में रूपांतरित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही या की गई पहलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, ब्राण्डकरण व पैकेजिंग पर विशेष जोर दे रही है। तदनुसार किसानों और विशेष रूप से युवाओं तथा महिलाओं को प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान से सशक्त बनाया जा रहा है। युवाओं के बीच केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए अनुकूल योजनाओं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, जोखिम प्रबंध, गौपशुओं तथा भैंसों की शुद्ध देसी नस्लों की सुरक्षा व ई–विपणन/ई–नाम के बारे में जागरूकता सृजित की गई है। उनका कहना था कि सरकार पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सकों या वीएलडीए को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शुरू करने पर कार्य कर रही है। ये शल्य चिकित्सक या वीएलडीए राज्य में डेयरियां स्थापित करने के लिए सरकार के प्रोत्साहनों में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राज्य में देसी गायों की डेरियां स्थापित करने के लिए अनुदान दे रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकार नकद प्रोत्साहन देकर गौ पालकों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति दिन 10 कि.ग्रा. से अधिक दूध देने वाली गायों को 20,000/–रु. का तथा प्रतिदिन 8 से 10 कि.ग्रा. दूध देने वाली गायों को 15,000 रु. व प्रतिदिन 6 से 8 कि.ग्रा. दूध देने वाली गायों को 10,000 रु. का नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

श्री राज नाथ सिंह ने खेती संबंधी नई–नई तकनीकों को अपनाने के लिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। यह देश के अन्य भागों के किसानों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने सशक्त 'वैज्ञानिक–कृषक सम्पर्क' पर बल दिया, ताकि खेती को प्रौद्योगिकी से संचालित बनाया जा सके। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि वैज्ञानिकों और नीति–निर्माताओं को नवोन्मेषी किसानों को उनकी बुद्धि के उपयोग में सहायता पहुंचानी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की नई पहलों से न केवल कृषि में एक अन्य क्रांति आएगी बल्कि इससे युवाओं को इस व्यवसाय में बने रहने के लिए भी प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने खेती से होने वाली आय को बढ़ाने हेतु कृषि विविधीकरण की दिशा में राज्य सरकार व किसानों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्हें प्रसन्नता थी कि हरियाणा में मंडियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा यह राज्य ई–नाम अपनाने के मामले में देश में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। उनके विचार से हरियाणा के किसान अन्य राज्य के किसानों को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हैं जिससे कृषि को और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है, द्वितीय पीढ़ी की तकनीकों को अपनाया जा सकता है, ताकि खेती की लागत कम हो सके, मिट्टी और पानी का उचित प्रबंधन किया जा सके, प्रसंस्करण, ब्राण्डकरण, पैकेजिंग, विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके व गुणवत्ता तथा एसपीएस के मुद्दों से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कृषि में जोखिम प्रबंधन तथा किसानों के कौशल के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने फील्ड कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इन सभी योजनाओं से किसानों को अवगत कराएं। उन्होंने मुख्यतः 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना', 'मुद्रा योजना', 'उज्ज्वला योजना' तथा 'अटल पेंशन योजना' जैसी योजनाओं पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई; बागवानी, डेरी और मात्स्यिकी के क्षेत्रों में विकास; भंडारण सुविधाओं, शीत श्रृंखला व ई–नाम के अंतर्गत मंडियों को जोड़ने के लिए बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इन सभी प्रयासों से किसान सशक्त होंगे तथा वे कृषि को और अधिक आकर्षक, प्रतिस्पर्धात्मक और लाभप्रद बनाने के लिए अपने खेती संबंधी दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

श्री सुभाष बराला, राज्य अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने कृषि तथा डेरी क्षेत्रों में महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया, ताकि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठा सकें। श्री देवेन्द्र चौधरी, सचिव, पशुपालन, भारत सरकार ने बताया कि देसी गायों जैसे गिर, साहीवाल, थारपार्कर, आदि के सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये गायें ए2 दूध उत्पन्न करने में सक्षम हैं जिसकी पूरे विश्व में बहुत मांग है। सरकार सभी राज्यों में दूध व दुग्धोत्पादों की खरीद व विपणन को विनियमित करने में बल दे रही है क्योंकि इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेंगे। श्री कृष्णपाल, राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कहा कि यूरिया, डीएपी आदि जैसे उर्वरक अब आसानी से मिल रहे हैं तथा उर्वरकों का मूल्य भी अब नियंत्रण में है। वे किसानों द्वारा खेती में विविधीकरण को अपनाने के कारण प्रसन्न थे।

डॉ. एस.एस. अहलुवालिया, राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कृषि में युवाओं की घटती हुई रूचि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं का कृषि में सदैव अधिक से अधिक योगदान रहा है, अतः उन्हें खेती की उन्नत तकनीकों व बाजार के अवसरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रतिस्पर्धी लागत और ब्राण्डकरण 'स्मार्ट कृषि' के अनिवार्य घटक बन गए हैं। उनका सुझाव था कि हरियाणा के कृषि मंत्री को छोटे कस्बों के निकट ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करनी चाहिए क्योंकि इससे ग्रामीण युवाओं की उन्नत खेती करने के प्रति रूचि जागृत होगी।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य महानुभावों में शामिल थे : श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार; श्री विपुल गोयल, उद्योग मंत्री, राज्य सहकारिता मंत्री; श्री मनीष ग्रोवर, मुख्य संसदीय सचिव; श्रीमती सीमा त्रिखा; विधायक, नामतः श्री मूलचंद शर्मा व श्री टेक चंद शर्मा; अध्यक्ष, एचएसएएमबी श्रीमती कृष्णा गहलावत, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेरी; श्रीमती रजनी सेखरी सिब्बल, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण; डॉ. अभिलक्ष लिखी एवं अन्य महानुभाव।

इस अवसर पर उन किसानों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने मुर्रा भैंसों, साहिवाल गायों और हरियाणा गायों जैसी श्रेष्ठ गुणवत्ता व उच्च दूध देने वाली पशु नस्लों को पाला था ।

इस अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने नई सोच की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि किसानों की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लक्ष्य का हवाला दिया और कहा कि जो नई पहलें लागू की जा रही हैं उनसे हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह उपलब्धि किसानों को समृद्ध बनाने, उन्हें उद्योगपतियों या व्यापारियों के समकक्ष बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। किसान समुदाय को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने पर जोर देते हुए चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने सुझाव दिया कि किसानों को उनकी फसल की बिक्री के बदले जो धनराशि दी जाती है वह भिन्न होनी चाहिए तथा बाजार में उसका मूल्य सामान्य धनराशि की तुलना में तीन गुना होना चाहिए। अपने सुझाव के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण दिया और बताया कि किसान पहले वर्ष केवल 10,000/–रु. बचा सकेंगे और दूसरे वर्ष 12000 से 15000 रु. की बचत करते हुए वे खेती के चौथे वर्ष में 25000 रु. तक की बचत करने में सफल होंगे, लेकिन फरीदाबाद में एक उद्योगपति का चार वर्षों में टर्न ओवर 4 करोड़ रुपये तक हो जाता है। उन्होंने कहा इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि किसानों की वास्तविक प्रगति तभी संभव होगी जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण होगा।

इस समारोह में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने भी भाग लिया जिन्होंने किसानों के लाभ के लिए केन्द्र सरकार की हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉ. ओ.पी. धनखड़ की भी प्रशंसा की जो किसानों की प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 30 प्रतिशत किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में इसके अंतर्गत लाए गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2017 तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 2018 तक 50 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने दुग्धोत्पादन के मामले में हरियाणा को देश का प्रथम राज्य बनाने में प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का भी आश्वासन दिया।

श्री ओ.पी. धनखड़ ने बताया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के एक तिहाई किसानों को लाया गया है और जो अभी इसके अंतर्गत नहीं आए हैं उन्हें भी गिरदावरी की पुरानी प्रणाली के अंतर्गत फसल की हानि होने पर प्रति एकड़ 12000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेत फसल और पशुधन का बीमा किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को हर प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। सरकार का लक्ष्य पॉलीहाउस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को जो वर्तमान में 5000 एकड़ है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख एकड़ करना है। सरकार ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है। राज्य की 108 मंडियों में से 37 को ई–नाम के साथ जोड़ा जा चुका है, 17 को जोड़ने का कार्य चल रहा है और शेष को मार्च 2018 के अंत तक जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के 6,62,641 किसानों ने ई–नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेची है और इस प्रकार 7,527 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है।

डॉ. धनखड़ ने सम्मेलन के प्रतिभागियों से उन किसानों का परिचय कराया जिन्हें फसलों का नुकसान होने पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में राशि प्रदान की गई है। ये हैं : चरखी दादरी के श्री राजसिंह जिन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16 हजार रुपये अदा करने के बाद 3,27,935 लाख रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार, शमशेर सिंह को 2.43 लाख रुपये, भगवाना को 1.80 लाख रुपये, सुरेन्द्र को 1.62 लाख रुपये और महेन्द्र सिंह को 1.62 लाख रुपये बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसलों को नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। यदि यह पिछले वर्ष गेहूं की फसल को हुए नुकसान के बराबर होता तो बीमा कंपनियों को 209 करोड़ रुपये के एवज़ में 2000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता।

उत्तर प्रदेश से आए सांसद श्री विरेन्द्र सिंह मस्त, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा, परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर ने भी किसानों को सम्बोधित किया।

खांडाखेड़ी गांव के एक किसान श्री जयपाल सिंह को ट्रैक्टर प्रदान किया गया। मंडी समिति के तीन सचिवों को ई–नाम के कार्यान्वयन में उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए मोटर साईकिलें प्रदान की गईं। इनके नाम हैं : चरखी दादरी की सुमन लता, सिरसा की जयवंती तथा सोनीपत के राकेश जैन। वे प्रगतिशील किसान जिन्हें ई–नाम के माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ था, उन्हें भी रोटावेटर प्रदान किए गए। इनके नाम हैं : चरखी दादरी के श्री राजेश व एलानाबाद के सतबीर सिंह व सफीदों के परमजीत। जिन व्यापारियों को किसानों को ऑन लाइन भुगतान करने के लिए लैपटॉप से सम्मानित किया गया उनमें चरखी दादरी के विकास गोयल और अमित मित्तल तथा सिरसा के जसप्रीत सिंह शामिल थे। इसी प्रकार, सहकारी क्षेत्र में प्रगतिशील किसानों को हरकोफेड, हारको बैंक, सुगरफेड, हैफेड और हरियाणा डेरी विकास सहकारी फेडरेशन की ओर से प्रत्येक के लिए 25000 रु. का नकद पुरस्कार दिया। किसानों को शहद रत्न पुरस्कार, खुम्बी रत्न पुरस्कार और मशरूम नेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जिन किसानों ने अपने मवेशियों के साथ पशु मेले में भाग लिया था उन्हें, प्रत्येक को 11,000/–रु. नकद प्रदान किए गए।

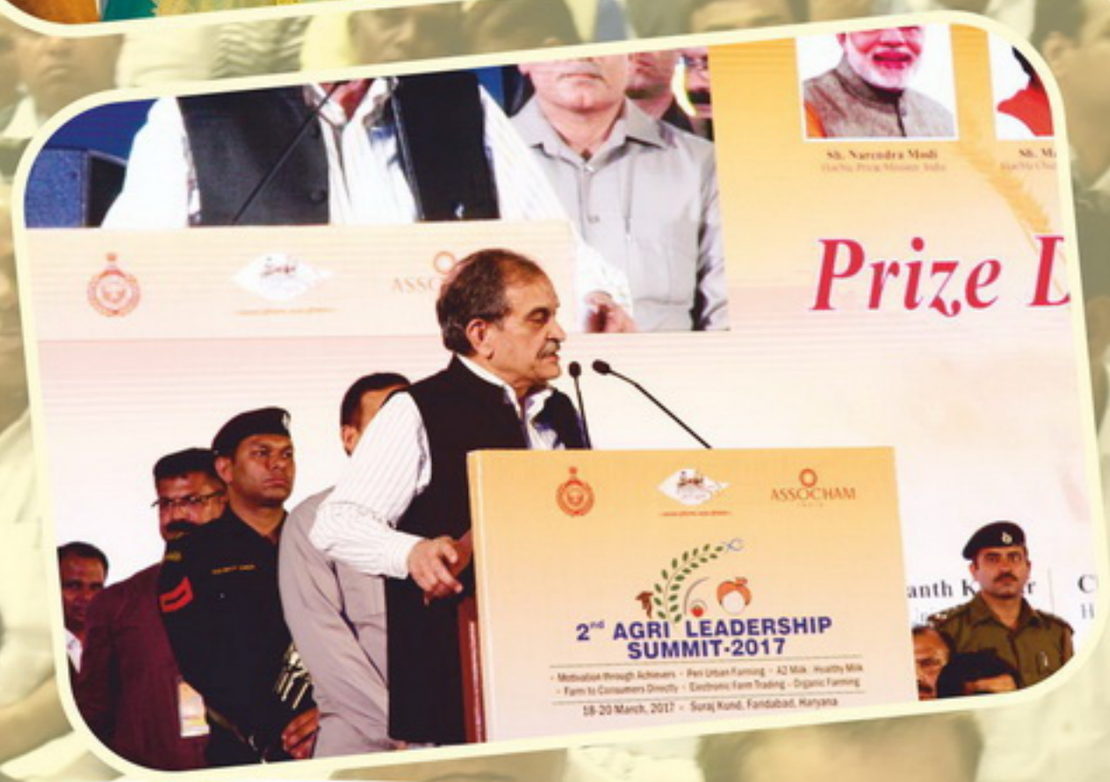
Prize L
ASSOCHAM
2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017
18-20 March, 2017 - Suraj Kund, Faridabad, Haryana

2nd AGR LE
SU MIT

समापन सत्र

समापन सत्र के मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी थे। इस सत्र में अनेक महानुभावों जैसे चौधरी बिरेन्द्र सिंह, मंत्री, भारत सरकार; कैप्टन अभिमन्यु, मंत्री, हरियाणा सरकार; श्री गौरी शंकर, मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार; श्री लक्ष्मी नारायण यादव, सांसद; विरेन्द्र सिंह, सांसद; श्री कृष्ण लाल पवार, मंत्री, श्री ओ.पी. धनखड़, मंत्री, हरियाणा सरकार, श्री रामबिलास शर्मा, मंत्री, हरियाणा सरकार और श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक ने भी प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। सभी का विचार था कि किसानों को प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने तथा उन्हें मंडियों से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। इन सभी ने हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओ.पी. धनखड़ की प्रशंसा की जिन्होंने इस आयोजन के लिए कठोर तथा निरंतर प्रयास किए।

हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो॰ कप्तान सिंह सोलंकी ने अपने समापन भाषण में भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों का उल्लेख किया कि भारत वैज्ञानिक रूप से एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए कारगर तकनीकें विकसित की हैं और इनमें कृषि भी शामिल है। गति बनाए रखने के लिए इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की बहुत जरूरत है। इससे स्वामी विवेकानंद के इस स्वप्न को साकार करने में मदद मिलेगी कि '21वीं सदी भारत की होगी'। उनका कहना था कि यदि हम सभी एक कदम आगे बढ़ें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार और विशेष रूप से कृषि मंत्री की उन योजनाओं को लागू करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जिनसे महिलाओं सहित किसान सशक्त होंगे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हरियाणा के किसान नई सोच वाले हैं और वे खेती में नई–नई खोजें कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ किसानों ने अपने उत्पादों के ब्राण्ड विकसित किए हैं और किसान बड़ी संख्या में कृषि में विविधीकरण को अपना रहे हैं।

इस राज्य के किसान ई–नाम के माध्यम से अपनी उपज को बेचने के मामले में अन्य राज्य के किसानों से काफी आगे हैं और गायों व भैंसों की देसी नस्लों के संरक्षण/सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने 'द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017' के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओ.पी. धनखड़ को बधाई दी और सुझाव दिया कि जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है हमें वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के वे शब्द याद दिलाए जिन्होंने कहा था कि 'जहां 17वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 18वीं शताब्दी फ्रांस की थी, 19वीं शताब्दी जर्मनी की थी और 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी वहां 21वीं शताब्दी भारत की होगी'।

उन्होंने द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उनका मानना है कि देश ऊर्जावान होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है और सरकार ने इस सम्मेलन के द्वारा किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखी पहल की है जिससे न केवल हमारे किसान बल्कि खेती तथा अन्य गतिविधियों से जुड़े अन्य सभी लोग भी इसमें भाग लेकर लाभान्वित होंगे।

इस सम्मेलन में हजारों किसानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार देने के अतिरिक्त माननीय राज्यपाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा राशि के चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर किसानों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित व पुरस्कृत किया गया।

श्री अजय गौड़, श्री निवास गोयल, श्री जी.एल. शर्मा, श्री पवन बेनिवाल, श्री चन्द्र प्रकाश कथुरिया और गुलशन भाटिया भी कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे।

Prize Distribution & Closing Ceremony
20 March 2017
Chief Guest :
Prof. Kaptan Singh Solanki
HE Governor, Haryana

Sh. Manohar Lal

खेती रत्न

हमारे कुछ अग्रणी व नवप्रर्वतक किसानों ने फार्म संबंधी नई खोजों तथा कृषि में विविधीकरण में स्वयं को सिद्ध किया है और उन्हें '**खेती रत्न**' के रूप में सम्मानित करते हुए इस सम्मेलन में 1,00,000/– रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

हमारे खेती रत्न हैं :–

नाम	पुरस्कार
श्री राजेश खेडी	जैविक खेती रत्न
सुश्री शिवानी महेश्वरी	फूल खेती रत्न
श्री बिशन पाल सिंह राणा	औषधि खेती रत्न
श्री सिलक राम धनखड़	सब्जी खेती रत्न
श्री राजेन्द्र कुमार शरण	शहद रत्न
श्री अनिल कुमार सैनी	मशरूम रत्न
श्री जयपाल सिंह	मत्स्य रत्न
श्री जगबीर देसवाल	मुर्गीपालन रत्न

विदेशी भागेदारी

कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017 को सुचारू रूप से तथा सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न बैठकों में विदेशों की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया तथा विदेशी प्रतिभागियों द्वारा कृषि, बागवानी, डेयरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि में हुई प्रौद्योगिकी प्रगतियों की साझेदारी की गई। इस संबंध में नई दिल्ली में विभिन्न देशों के दूतावासों में संबंधित प्राधिकारियों के बीच अनेक बैठकें आयोजित हुईं। एचएसडब्ल्यूसी अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल 'एसोचैम' के साथ विभिन्न दूतावासों में संबंधित कृषि काउंसेलरों से मिला तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल ने दूतावासों से अनुरोध किया कि वे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017 में पूरे समर्पण से भागीदारी करें। दूतावास सैद्धांतिक रूप से सहमत थे, लेकिन चर्चा में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि दूतावासों को शामिल करने का जो समय निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है। दूतावास के लोगों की एकमत राय थी कि इस प्रकार के कृषि शिखर सम्मेलनों से जो जानकारी उभरकर सामने आती है उसे राज्य सरकार को कम से कम 6–8 महीने पहले भेजा जाना चाहिए तथा विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से संबंधित सभी मुद्दों को जैसे सेमिनारों में भाग लेना, स्टाल लगाना, स्काइपे प्रस्तुतीकरण कम से कम 90 दिन पहले अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। तथापि, विभिन्न दूतावासों के लोगों से सम्पर्क करने के गहन प्रयास किए गए तथा अत्यधिक प्रयासों के पश्चात् 9 देशों के 14 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

पशु प्रदर्शनी

इस अवसर पर एक पशु प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान अपने पशु लेकर आए। कुल 25 करोड़ रुपये मूल्य का मुर्रा सांड शहंशाह इस तीन दिवसीय द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2017 में आकर्षण का मुख्य केन्द्र था। जैसा कि ज्ञात है यह सम्मेलन 18–20 मार्च 2017 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सूरजकुण्ड, फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। शहंशाह के मालिक श्री नरेन्द्र सिंह जिनका पानीपत जिले के दिदवारी गांव में अपनी गोलू डेरी फार्म है, ने बताया कि चार वर्ष आयु के शहंशाह को उत्तर प्रदेश में 2016 में आयोजित सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में ताज से नवाजा गया था। यह पशु 5 फुट 10 इंच ऊंचा है और इसकी पूंछ से सिर तक की लंबाई 15.5 फुट है। शहंशाह की मां एक दिन में 27 किलो दूध देती है। शहंशाह के दैनिक आहार में 10 कि.ग्रा. दूध और आधा कि.ग्रा. शुद्ध देशी घी शामिल है। श्री नरेन्द्रं सिंह ने यह भी बताया कि वे पशुओं के गुणवत्तापूर्ण प्रजनन में रत हैं और उनके डेरी फार्म में कुल 180 दुधारू पशु हैं जिनमें भैंसें और गाय शामिल हैं।

एक अन्य सांड जिसका नाम रुस्तम था और जिसके स्वामी गटौली गांव के श्री दलेल सिंह हैं, भी इस सम्मेलन में आकर्षण का केन्द्र था। रुस्तम की आयु 4.5 साल है, ऊंचाई 5.7 फुट है तथा पूंछ से सिर तक की लंबाई 16.5 फुट है। उसके दैनिक आहार में 20 कि.ग्रा. दूध, गाजर और फल शामिल हैं। श्री दलेल सिंह ने बताया कि रुस्तम को दिसम्बर 2016 में मुक्तसर, पंजाब में आयोजित नौवीं राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि वे रुस्तम का वीर्य बेचकर प्रति वर्ष 50 लाख रुपये कमाते हैं।

कैथल जिले के बुद्धखेड़ा गांव से आया एक अन्य सांड सुल्तान भी आकर्षण का केन्द्र था। इसकी ऊंचाई 6 फुट, पूंछ से सिर तक की लंबाई 16 फुट और वज़न 17 क्विंटल था।

IP

Healthy Milk
ganic Farming

18-20 March, 2017 • Suraj Kund, Faridabad, Haryana

|| बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ||

IVE CATTLE SHOW

TRANSFORMING HARYANA - PROGRESSING HARYANA

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

मुख्य उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्र के खाद्यान्न भंडार ने 112.94 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदाता
- बासमती चावल के निर्यात में प्रथम देश से कुल निर्यात किए जाने वाले चावल में हरियाणा का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा
- राज्य की स्थापना से लेकर खरीफ 2013 तक की अवधि के दौरान 39.89 लाख मीट्रिक टन चावल का सर्वोच्च उत्पादन रिकॉर्ड किया गया।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन
  - ➢ खरीफ 2016 के दौरान 7.26 किसानों और 11.92 लाख हैक्टर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया गया।
  - ➢ रबी 2016–17 के दौरान 5.7 लाख किसानों और 9.60 लाख हैक्टर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया गया।
- कपास की फसल में बीमा भुगतान पर राज्य सरकार अतिरिक्त 3% अनुदान दे रही है।
- 15.73 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए।
- राज्य में 34 अचल और 2 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।
- जैविक खेती का प्रवर्धन। 12 जिलों में प्रत्येक में 50 एकड़ के 20 क्लस्टर जैविक खेती के लिए चुने गए।
- सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का कार्यान्वयन
- जलवायु आधारित गाँव योजना के लिए ₹ 200 करोड़ का प्रावाधान किया गया।
- सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अर्न्तगत 36 खण्डों की पहचान की गई।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

किसान भवन, सैक्टर 21, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष 0172–2571553, 2571544
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : agriharyana2009@gmail.com
• वेबसाइट : www.agriharyana.nic.in; www.agriharyanaofwm.com; www.agriharyana.in

प्रदर्शनी

यह प्रदर्शनी द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन–2017 का एक सफल आयोजन था। इसमें अनेक प्रदर्श प्रदर्शित किए गए तथा अनेक किसानों/आगंतुकों को विभिन्न स्टालों में रूचि लेते हुए देखा गया। किसानों के आकर्षण का केन्द्र मुर्रा नस्ल का सांड शंहशाह था जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये थी, जैसा कि इसके स्वामी ने दावा किया था। एक अन्य मुर्रा सांड जिसका नाम रुस्तम था, 5 फुट 7 इंच ऊंचा और 16 फुट 5 इंच लंबा था। इसके स्वामी गटौली गांव के श्री दलेल सिंह थे जो स्वयं आकर्षण का केन्द्र थे। बीसीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टाल को अनेक किसानों ने देखा। बीसीएस ने रीपर बाइंडर, पावर टीलर,पावर वीडर, डिस्क मॉवर और फोडर हार्वेस्टर आदि का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में एक अन्य आकर्षण करनाल के एल्ले मशरूम थे जिन्होंने खुम्बी की सस्योत्तर प्रौद्योगिकी के मामले में अपनी सफलता की कहानी से अन्य किसानों को प्रोत्साहित किया। कन्हरा गांव जिला दादरी के ग्रांम आधारित उद्यम 'प्योर एंड श्योर एग्रोबेस्ड प्रा. लिमिटेड' ने जैविक खेती के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। बागवानी के समेकित विकास हेतु मिशन, बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश ने अपनी बागवानी उपज व सस्योत्तर उत्पादों का प्रदर्शन किया। फरीदाबाद जिले के महिला समूह द्वारा चलाए जा रहे एक स्वयं सेवी संगठन एसएमआर ग्रुप ने औषधीय पौधों से तैयार पैक बंद उत्पाद प्रदर्शित किए। इसी प्रकार, पानीपत के एक डीलर हरियाणा एग्रो सिस्टम्स ने छिड़काव पम्प, ड्रिप तथा मिनी स्प्रिंकलर, सिंचाई रोटावेटर तथा कुछ ऐसे कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जो बहुत उपयोगी थे और जिन्हें अनेक किसानों/आगंतुकों ने अत्यंत रूचि के साथ देखा। विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे हरियाणा किसान आयोग, कृषि विभाग हरियाणा, बागवानी समेकित विकास के लिए मिशन, बागवानी विभाग, हरियाणा तथा तीन विश्वविद्यालयों, नामतः चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय तथा बागवानी विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी स्टालों को भी अनेक किसानों/आगंतुकों ने देखा। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रदर्शनी स्टाल भी थे जो अचार, मुरब्बा,जैम, कैंडी तथा अन्य परिरक्षकों को प्रदर्शित कर रहे थे। इन स्टालों पर घरेलू उपयोग की सामग्री प्रदर्शन व बिक्री के लिए रखी गई थी।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
HARYANA

, New Delhi-110037
Haryana-124001
5886, 9215593500
NABCONS

कृषि यंत्रों की विस्तृत श्रृंखला
CONFERENCE HALL
मुख्य विशेषताएं

AMBRA
NEW HOLLAND 3032
NEW HOLLAND
AGRICULTURE
जान भी, शान भी!

रेही, नमी, Salt आदि)
वैदिक प्लास्टर से समाधान
VEDIC PLASTER

मुख्य उपलब्धियां

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी सी डी पी)

- स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के तहत एक नई योजना जो कि भारत वर्ष में पहली बार 1 अप्रैल 2017 को राज्य मे लागू की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत 140 बागवानी फसल के विशिष्ट समूह में से 340 बागवानी गाँव का राज्य में विकास होगा जो कि बाजार से सीधा संबंध रखेंगे।
- कार्यक्रम तीन साल तक जारी रहेगा। प्रत्येक समूह विपणन संरचना और फसल सस्योतर प्रबंधन जैसे कि पैक हाउस, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र छँटाई मशीन, भंडारण सुविधाओं, वैन, निवेश और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।
- तीन साल तक 510 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
- लघू किसान कृषि हरियाणा (एसएफएसीएच) के तहत 20 किसानों के उत्पादक संगठन के माध्यम से सब्जियों और फलों के लिये लागू की जायेगी। जिसमें 702 किसान इच्छुक समूह जिसमें 12923 किसान शामिल है।

शो / एक्सपो

- आम मेला : 2 से 3 जुलाई 2016 को पिंजोर गार्डन में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया।
- सब्जी–मशरूम और शहद पर 17 से 19 दिसम्बर 2016 को सब्जियों के लिये उत्कृष्ट केन्द्र धरौडा (करनाल) में आयोजन किया गया।
- 29–30 दिसम्बर 2016 को फल एक्सपो फलों के लिये उत्कृष्टता केन्द्र मांगियाना (सिरसा) में आयोजन किया गया।

आई टी पहलः

- एमआई नेट पोर्टल सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन और अनुदान के फैलाव के लिये लॉन्च और संचालित
- हॉर्टनेट सफलतापूर्वक एन एच एम गतिविधियों के लिये शुरू किया गया।
- नर्सरी और बीज लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन और प्रगति पोर्टल ऑनलाइन आवेदन के लिये पॉली नेट पोर्टल सफलतापूर्वक लॉन्च और संचालित।

बागवानी विभाग, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

उद्यान भवन, सैक्टर 21, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172–2582322, 2587570

• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : hortharyana@gmail.com

• वेबसाइट : www.hortnet.gov.in; www.minet.hortharyana.gov.in; www.polynet.hortharyana.gov.in

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

इस कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में विधान सभा के अध्यक्ष श्री कंवर पाल, उपाध्यक्ष, श्रीमती संतोष यादव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री ओ.पी. धनखड़ और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में हरियाणा में कृषि को नई दिशा देने के लिए 19.03.2017 को तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

एक समझौता ज्ञापन जो कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए था, पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल तथा वेजेनिंजन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड के हस्ताक्षर हुए। कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रो. के.पी. सिंह व नीदरलैंड दूतावास के श्री आनंद कृष्णन ने विश्वविद्यालयों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कृषि एवं विकास पर एक अन्य समझौता भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) और हरियाणा बागवानी विभाग के बीच हुआ। इस समझौता ज्ञापन पर प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, डॉ. अभिलक्ष लिखी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएससीआई, श्री सतेन्द्र आर्य द्वारा क्रमशः हरियाणा सरकार और एएससीआई द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक अन्य समझौता ज्ञापन केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), मुम्बई और हरियाणा के मात्स्यिकी विभाग के बीच हुआ। निदेशक, मात्स्यिकी श्री आर.के. सांगवान ने इस समझौते पर विभाग की ओर से जबकि कुलपति सीआईएफई डॉ. गोपाल कृष्णन ने सीआईएफई की ओर से हस्ताक्षर किए।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

सेमिनार

विषय : ए2 दूध : स्वस्थ दूध

दुग्धोत्पादन में क्रांति

सत्र के अध्यक्ष श्री ऋषि प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड ने प्रतिभागियों को विषय से परिचित कराया तथा बेहतर अनुकूलन, क्षमता परीक्षण, रोग–प्रतिरोध व उच्च वसा अंश बनाम संकर नस्लों की दृष्टि से गायों की देसी नस्लों से राज्य में दुग्धोत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा किसानों को अपनी आजीविका के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर डेयरी फार्मिंग को अपनाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके।

एनडीडीबी के डॉ. ए.पी. सिंह ने बेहतर उत्पादकता और लैंगिक स्वास्थ्य व प्रजनन गतिविधि बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर पशु आहार में खनिज मिश्रण के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने डेरी पशुओं को संतुलित आहार देने पर बल देते हुए किसानों को यह परामर्श दिया कि वे अधिक चराई से बचें क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पशु मोटे हो जाते हैं और इससे लाभ की बजाय हानि ज्यादा होती है।

डॉ. भूषण त्यागी, सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे पत्र में दुग्धोत्पादन बढ़ाने और इसके साथ ही देसी नस्लों के संरक्षण के लिए पशुपालन और डेयरी के केन्द्रीय विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा दिया। इस दिशा में की गई कुछ नई व महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय कामधेनू प्रजनन केन्द्र
2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
3. गोकुल ग्राम
4. वीर्य लिंगीकरण केन्द्रों की स्थापना
5. स्वपात्रे निषेचन प्रयोगशालाओं की स्थापना

कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी है और इसके पूरी तरह विकसित होने पर दुग्धोत्पादन में कम से कम 10–20 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

सेमिनार

विषय : ए2 दूध : स्वस्थ दूध

गोपशु तथा जैविक खेती : मूलभूत तथ्यों पर लौटना

आरंभ में, अध्यक्ष, गौसेवा आयोग, श्री भानी राम मंगला जी ने दूध, भार वहन, जैविक खाद तथा आग के लिए ईंधन से युक्त हमारी पुरानी परंपरागत और टिकाऊ खेती की याद दिलाई। अब जब पर्यावरण बिगड़ रहा है और मिट्टी की दशा भी खराब हो रही है, इस प्रकार के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा रहा है, ताकि इन संसाधनों को और अधिक हानि न पहुंचे तथा आने वाले समय में फसलोत्पादन को टिकाऊ बनाया जा सके। डॉ. हरिओम ने जैविक खेती के विभिन्न घटकों जैसे पशुओं, मिट्टी और पानी के संसाधनों, जैविक पोषक तत्वों, फसलों और फसल अपशिष्टों के प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये घटक अब बहुत अनिवार्य हो गए हैं। किसानों को जैविक खेती की दिशा में प्रेरित करने के लिए अनेक खेत प्रयोगों तथा किसानों की सफलता की कहानियों का उल्लेख किया गया है। श्री करन सीकरी ने जैविक खेती के साथ गौशालाओं के एकीकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया। आदर्श गौशाला की संकल्पना ने गौपशुओं के लिए आरामदायक स्थितियां तैयार करना, जैविक आहार तथा चारा, स्वच्छता तथा सफाई का सुझाव दिया गया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया कि राज्य में कुल जैविक पदार्थों के उत्पादन तथा कुल भूमि क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग को राज्य सरकार सहायता पहुंचा रही है तथा राज्य में बड़े पैमाने पर जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

डा. विनोद पटेल, जेके ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ ने भारतीय नस्ल की विभिन्न लोकप्रिय गायों जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, थारपार्कर, राठी, गिर तथा विदेशी संकर नस्ल, होल्सटेइन फ्रेसियन के आनुवंशिक सुधार में अपने अनुसंधान संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक को बताते हुए डिम्ब के निष्कर्षण के लिए स्वस्थ व सक्षम दूध देने वाले गायों और सांडों का उपयोग किया जा रहा है। इन डिम्बों की स्वपात्रे छंटाई की गई है और सक्षम दाताओं से प्राप्त हुए शुक्राणुओं का उपयोग करते हुए निषेचन के लिए छांटा और चुना गया है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से इस प्रकार के निषेचित डिम्बों को चुनी हुई गायों के गर्भाशयों में रखा गया है और इस प्रकार सक्षम दाताओं की नस्ल को बढ़ाया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा डेयरी किसानों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से उन्नत गाय प्रजनित की गई हैं। इस प्रकार की सुविधाएं महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में भी उपलब्ध कराई गई हैं।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

मुख्य उपलब्धियां

- पशु पालन का राज्य के कृषि जीडीपी में लगभग 35 प्रतिशत योगदान है।
- वर्ष 2015–16 में कुल वार्षिक दुग्धोत्पादन राज्य में 83.8 लाख टन तक पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप इस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ी है और यह राज्य इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
- राज्य में वार्षिक अंडा उत्पादन 49133 लाख है।
- 'जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा' योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जाति के परिवारों के पशुधन का निःशुल्क बीमा किया जाएगा।
- गायों के वध पर पूर्णतः प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम' 2015 अनुसूचित किया गया है।
-
- सरकार 5 दुधारू पशुओं तक देसी गायों की डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।
- हरियाणा और साहीवाल नस्लों के निष्पादन की रिकॉर्डिंग शुरू की जा चुकी है। देसी गायों के स्वामियों को दुग्ध प्राप्ति के आधार पर 10,000/–रु. से 20,000/–रु. तक के आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
- समेकित मुर्रा विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
- लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला हिसार में रखी जा चुकी है।
- सरकार ने राज्य में गौवंश के कल्याण व रखरखाव के लिए गौ सेवा आयोग गठित किया है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा

पशुधन भवन, बेज़ 9–12, सैक्टर 2, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172-2574662 फैक्स : 0172-2586837
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : pashudhanhar@rediffmail.com
• वेबसाइट : www.pashudhanharyana.gov.in

पशुपालन एवं डेयरी में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रगतियां

सत्र के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत शर्मा, कुलपति, एलयूवीएएस, ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि पशु पालन और डेयरी भारत में अत्यधिक असंगठित क्षेत्र है लेकिन इसमें निवेश पर उच्च लाभ देने तथा कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के कार्य बल को रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2015–16 में 835 ग्रा./दिन हो गई है जो 1966–67 में केवल 130 ग्रा. थी। मुर्रा, साहिवाल, हरियाणा नस्लों के संरक्षण, सुधार की दिशा में राज्य में तेजी आई है तथा युवा डेयरी व्यवसाय अपनाने को प्रेरित हुए हैं। राज्य के शिक्षित युवाओं द्वारा कई अति अत्याधुनिक डेयरियां स्थापित की गई हैं। उनका विचार था कि इन उपलब्धियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान तथा युवाओं को कृषि में बनाए रखने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सस्ती रोग निदानिक किटें और ए2 दूध (जिसमें बीटा–केसिन प्रोटीन के ए2 प्रकार की उपरोक्तता है) एलयूवीएएस द्वारा विकसित की गई हैं और इनसे डेयरी किसानों व उपभोक्ताओं को बहुत सहायता मिलेगी। श्री एर्ल रत्तरे, न्यूजीलैंड ने बिंसार फार्मस, न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग पर एक बहुत अच्छा प्रस्तुतीकरण दिया। यह निजी क्षेत्र का फार्म है। हरियाणा में इस प्रकार के फार्म स्थापित करने के सहयोगी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताजे सुरक्षित और शुद्ध दूध की मांग विश्वभर में बढ़ रही है। भारत को इस बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे से लैस होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आहार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, दुग्धोत्पादन, जनकता और संतति, आनुवंशिक श्रेष्ठता आदि पर रिकॉर्ड रखना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। मैडम रजनी शेखरी सिब्बल, आईएएस, सचिव, पशु पालन, हरियाणा ने कहा कि अनुसंधान में भावी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। राज्य के लगभग दो तिहाई किसान सीमांत और छोटे किसान हैं। उनकी आवश्यकताएं अन्य किसानों की तुलना में भिन्न हो सकती हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉ. रविन्द्र शर्मा, निदेशक, अनुसंधान, एलयूवीएएस ने उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में बताया और कहा कि विश्वविद्यालय, हरियाणा को गोपशुओं और भैंसों के सभी प्रमुख रोगों से मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। राज्य में खनिज तत्व की कमी वाले विभिन्न क्षेत्रों के पशुओं के लिए खनिज मिश्रण तैयार किए गए हैं। उनका सुझाव था कि एंटिबायोटिक्स का उपयोग केवल पशुचिकित्सकों की सिफारिशों पर ही किया जाना चाहिए।

डॉ. आर.एस. डाबर, विभागाध्यक्ष, पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी ने कहा कि अनेक युवा किसान डेयरी को व्यापार के रूप में अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं और वे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले पशुओं को पाल रहे हैं। ये सभी स्वच्छता बनाए रखने, प्रगत प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों, उत्पादन की श्रेष्ठ विधियों, मंडी की आवश्यकताओं, पैकेजिंग, ब्राण्डकरण और विपणन आदि तकनीकों को जानने के बारे में रुचि ले रहे हैं। फोर्टिफाइड, जैविक तथा ए2 दूध (इसमें मुख्यतः बीटा–केसिन प्रोटीन का ए2 प्रकार होता है और जिससे शरीर की रोगरोधी प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है) बड़े विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। उनका सुझाव था कि किसानों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए अन्यथा कोका कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस व्यापार को भी हथिया लेंगीं। डॉ. बी.एल. पाण्डर, विभागाध्यक्ष, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन ने अपने प्रस्तुतीकरण में सदन को बताया कि हरियाणा में कुल दुग्धोत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत गायों से और 51 प्रतिशत भैंसों से प्राप्त होता है। गाय की साहीवाल, गिर, थारपार्कर, राठी, हरियाणा, लाल सिंधी आदि नस्लें और भैंस की मुर्रा, नीली रावी नस्लें हरियाणा के कृषकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पशुधन मिशन के अंतर्गत इन उन्नत नस्लों को संरक्षित करने और सुधारने के अनेक प्रयास किए गए हैं। इस प्रयास में समुदाय आधारित कार्यक्रम लागू किए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गोबर और मूत्र को एकत्र करने के लिए संकलन केन्द्रों के अलावा आवारा पशुओं का प्रबंध करने के लिए और इसके साथ–साथ डेयरी पर्यटन को बढ़ावा देने, आधार के पैटर्न पर गोपशु कार्ड बनाने और लोगों व विशेषकर महिलाओं को डेयरी संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र खोले जाने चाहिए।

ASSOCHAM
INDIA
2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017
• Motivation through Achievers
• Farm to Consumers Directly
• A2 Milk : Healthy Milk
• Organic Farming
18-20 March, 2017

2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017
• A2 Milk : Healthy Milk
• Organic Farming

किसानों की आय दुगुनी करना

इस विषय पर चर्चा डॉ. आर.के. खटकर, पूर्व प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने आंरभ की और उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि राज्य है लेकिन यहां इस क्षेत्र के लिए कुल बजट का मात्र 1.48 प्रतिशत ही आवंटित किया गया है, अतः इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन/खरीद मूल्यों में तर्कसंगत वृद्धि के बिना उत्पादन लागत बढ़ रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में बाधक है। वैज्ञानिक स्तर पर भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का पर्याप्त न होना व प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंध न होना ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने ठेके पर खेती तथा सहकारी विपणन पर भी चर्चा की ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके।

डॉ. एम.एस. चौहान, निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा ने कहा कि बकरी पालन का स्तर अब बदल गया है क्योंकि पहले इसे गरीब लोगों का व्यवसाय माना जाता था। चिकित्सीय महत्व के कारण बकरी का दूध सबसे महंगा है। जब डेंगू रोग का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था तो बकरी के दूध के भाव 300 रु./लिटर तक हो गए थे। भारत में बकरे–बकरियों की संख्या 13.5 करोड़ है जो छब्बीस श्रेणियों में वितरित है। भारत में प्रतिवर्ष 5.5 लाख टन बकरी के दूध का उत्पादन होता है। देश की लगभग 7 करोड़ जनसंख्या इस उद्यम से संबंधित है।

डॉ.के.एस. बांगरवा, अध्यक्ष, वानिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने आमदनी बढ़ाने के लिए वानिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि उचित वृद्धि तथा उपयुक्ततम उत्पादन के लिए कृषि, जलवायु की दृष्टि से अनुकूल फसलें और पौधे उगाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पोपलर खेती से प्राप्त होने वाली उपज से चावल–गेहूं फसल क्रम से प्राप्त होने वाली उपज की तुलना में प्रति हैक्टर अधिक लाभ प्राप्त होता है।

डॉ. गिरीश नागपाल, डीडीए (मुख्यालय), ए और एफडब्ल्यू ने कहा कि जल की प्रति बूंद से अधिक अनाज प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की उपज के लिए उन्हें बेहतर कीमतें दिलाना, उन्नत मंडियां और मूल्यवर्धन किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसा उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा।

सत्र के अध्यक्ष, माननीय डॉ. के.पी. सिंह, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने अपनी समापन टिप्पणी में बाजारों में उत्पाद ले जाने के पूर्व बाजार सर्वेक्षण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपभोक्ता दिन–ब–दिन गुणवत्ता और किस्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को औसत गुणवत्ता वाले उत्पादों की तुलना में अधिक मूल्य मिलता है और इस प्रकार इनसे किसानों की आमदनी पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सूचित किया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए समेकित फार्मिंग प्रणाली सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य स्तर पर सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है ताकि इसे किसानों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर
सम्मेलन-2017

मुख्य उपलब्धियां

सरकार को प्रस्तुत रिपोर्टें :

आयोग द्वारा अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यदल गठित किए गए। उन्होंने सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी रिपोर्टें सौंपी हैं। ऐसी आशा है कि इन रिपोर्टों से कृषि को ऊर्जावान और लाभदायक व्यवसाय बनाने हेतु कार्यनीतिपरक नियोजन में सहायता मिलेगी।

1. हरियाणा राज्य की कृषि नीति का मसौदा
2. किसानों के साथ परिचर्चा पर आधारित पर नीतिगत बिन्दुओं व विकल्पों पर रिपोर्ट
3. हरियाणा में कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए मुद्दों एवं विकल्पों पर रिपोर्ट
4. हरियाणा में टिकाऊ फसलोत्पादन के लिए संरक्षित कृषि पर रिपोर्ट
5. हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर रिपोर्ट
6. हरियाणा में मात्स्यिकी विकास पर रिपोर्ट
7. हरियाणा में बागवानी विकास पर रिपोर्ट
8. हरियाणा में सुरक्षित खेती के विकास पर रिपोर्ट
9. हरियाणा में पशुपालन के विकास पर रिपोर्ट
10. हरियाणा में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर रिपोर्ट
11. हरियाणा में बारानी क्षेत्र विकास पर रिपोर्ट
12. हरियाणा में किसानों को बाजार के साथ जोड़ने पर रिपोर्ट
13. हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्य वर्धन पर रिपोर्ट

वर्तमान में कार्यरत तकनीकी कार्यदल

वर्तमान में निम्न चार तकनीकी कार्य दल कार्यरत हैं ये कार्य दल किसानों, वैज्ञानिकों तथा फील्ड अधिकारियों के साथ चर्चाएं और बैठक कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

1. **हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना**
2. **हरियाणा में कृषि विस्तार**
3. **हरियाणा में परिनगरीय क्षेत्रों में कृषि का विविधीकरण**
4. **हरियाणा में दुधारू गोपशुओं और भैंसों से संबंधित पशु पोषण**

हरियाणा की टिकाऊ भूमि उपयोग संबंधी योजना

हरियाणा किसान आयोग ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एचएआरसीएएस), हिसार के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है।

एचएआरएससीए ने यह परियोजना पूरी कर ली है तथा इसे सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए हरियाणा किसान आयोग को सौंप दिया है। एचएआरएससीए ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए भूमि उपयोग योजना तैयार की है। इस परियोजना में हरियाणा में कृषि के विकास के लिए टिकाऊ भूमि उपयोग हेतु ब्लॉक विशिष्ट सिफारिशें की हैं। परियोजना द्वारा की गई सिफारिशों को कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा लागू किया जाना है, ताकि राज्य में कृषि का सकल विकास हो सके।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत तक कम कर दी गई है।
2. कृषि ऋण लेने पर स्टैम्प ड्यूटी हटा दी गई है।
3. लगभग सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
4. लगभग सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं।
5. राज्य पशुधन मिशन शुरू किया गया है।
6. मछली तालाबों के लिए जल प्रभार की दरें बहुत कम की गई हैं।
7. धान और गेहूँ प्रणाली में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान की खेती वाले क्षेत्र को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
8. चारा बीज उत्पादन के लिए रोलिंग योजना तैयार की जा रही है।
9. फलों तथा सब्जियों को अलग करते हुए एपीएमसी अधिनियम सुधारा जा रहा है।
10. सब्जी और फलों पर मण्डी शुल्क माफ कर दिया गया है।
11. एडीओ के वेतनमान संशोधित किए गए हैं।

हरियाणा किसान आयोग

अनाज मण्डी, सैक्टर 20, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172-2551764 फैक्स : 0172-2551864
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : haryanakisanayog@gmail.com
• वेबसाइट : www.haryanakisanayog.org

हरियाणा का भूदृश्य परिवर्तित करने के लिए बागवानी

हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार यादव ने हरियाणा राज्य में बागवानी की प्रगति के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। किसानों से नई विकसित होती हुई तकनीकों और सरकार द्वारा की गई पहलों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कहा गया है। डॉ. बी.एस. तोमर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिनगरीय जैविक सब्जी उत्पादन की क्षमता के बारे में बताया। कृषि विविधीकरण व विशेष रूप से बागवानी फसलों के माध्यम से विविधीकरण; अंतर फसलन या साथी फसलें उगाना, रिले फसलन व बेमौसमी एवं सुरक्षित खेती के साथ–साथ उच्च मूल्य वाली फसलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मंडियों में अपनी पैठ बनाने की अपार क्षमता है। यदि इस क्षेत्र में खेती करने वालों द्वारा सक्षम फसलें, किस्में, प्रौद्योगिकियां आदि अपनाई जाएं तो यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने इस क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने पर विशेष बल दिया। रोपाई के समय, क्रियाविधियों, पोषक तत्वों, सिंचाई तथा पादप सुरक्षा प्रबंध आदि से संबंधित अनेक किस्मों व प्रौद्योगिकियों में सटीकता प्राप्त की गई है और अब ये किसानों के लिए उपलब्ध हैं जिनसे वे बहुत फायदा उठा सकते हैं। डॉ. एस.एस सिंधु ने सब्जी और पुष्प फसलों की अंतर फसलन तथा साथी फसलन प्रणालियों पर प्रकाश डाला जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में सर्वोच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने किसानों की सफलता की श्रेष्ठ कहानियों का वर्णन किया और कहा कि जिन किसानों ने ऐसी फसल प्रणालियां अपनाई हैं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। भली प्रकार तैयार किए गए अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उन्होंने दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रगामी पथ पर बढ़ने वाले फार्मिंग पैटर्न की प्रशंसा की। उनका कहना था कि सब्जियों और फलों की न केवल स्थानीय मांग बढ़ी है बल्कि क्षेत्र से उनका निर्यात भी हो रहा है। डॉ. एस.के. सहरावत ने डॉ. सिंधु के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान विभिन्न नई पुष्प फसलों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण फूलों की रोपण सामग्री का बड़े पैमाने पर प्रगुणन होना चाहिए अन्यथा उनका प्रवर्धन नहीं हो पाएगा। इसके लिए उचानी/घरोंदा में बागवानी निदेशालय तथा हिसार में जैवप्रौद्योगिकी व पादप ऊतक संवर्धन केन्द्र द्वारा ऊतक संवर्धन तकनीकों के माध्यम से सफल प्रयास किए जा रहे हैं। किसान इन केन्द्रों से रोपण सामग्री खरीदकर बेहतर लाभ कमा सकते हैं। डॉ. राशा ओमर ने पूरे विश्व में बागवानी में हुए विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य एवं कृषि संगठन या एफएओ के कृषि विभाग हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) द्वारा सहायता में वृद्धि की जा रही है और भारत के मामले में ऐसा सभी कृषि संबंधित कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। बढ़ी हुई धनराशि से भारत के लिए आईएफएडी कार्यनीति पर भावी सहयोग के लिए प्रकाश डाला गया। यह एजेंसी व्यावहारिक क्षेत्रों में कृषि शिक्षा व अनुसंधान हेतु ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसने बारानी क्षेत्रों, समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, छोटे किसानों, महिलाओं, आदिवासी केन्द्रों, गृह कचरे पर आधारित जैवगैस इकाइयों, मनरेगा, कूंओं के पुनर्भरण, सूक्ष्म–सिंचाई, क्षमता निर्माण, जल प्रबंधन, संरक्षण एवं सहकारी फार्मिंग प्रणाली आदि पर विशेष ध्यान दिया है। श्री अमित वात्सायन ने बागवानी फसलों के लिए फसल मूल्य श्रृंखला तथा मंडी में पहुंच की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि इस मामले में पिछले कई दशकों के दौरान क्षेत्र और उत्पादन में क्रमशः 22 और 38 गुनी वृद्धि हुई है तथा कृषक उपज संगठनों (एफपीओ) ने भी 16 गुनी वृद्धि हुई है। आपूर्त श्रृंखला संबंधी सम्पर्कों को बढ़ाने के लिए ऋण संबंधी सम्पर्कों, जैविक प्रमाणीकरण के लिए संस्थागत क्रियाविधियों, मंडियों तक आसानी से पहुंच, परंपरागत भंडारण व कोठाड़ों, फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) छोटे किसानों की कृषि व्यापार सहकारिताओं (एसएफएसी) को सबल बनाने की आवश्यकता है। डॉ. सतेन्द्र सिंह आर्य ने भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) की गतिविधियों के बारे में बताया तथा कहा कि हरियाणा के व्यक्तियों अर्थात् प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों, दोनों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु हरियाणा कौशल परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि एएससीआई किसानों, कृषि श्रमिकों की क्षमता निर्माण, संगठित और असंगित कृषि से संबंधित उद्योगों के विकास, युवाओं में स्व रोजगार या बेरोजगारी, छात्रों तथा विस्तार कर्मियों के लाभ के लिए क्षमता निर्माण हेतु भारत में कौशल संबंधी रूपांतरण करने में रत है। यह मंत्रालयों, संस्थाओं, सेना, राज्य सरकार के विभागों, विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापनों के माध्यम से समन्वयन कर रही है। यह संस्था मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, सूअर पालन तथा अन्य कृषि संबंधी कार्यों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों की स्थापना के लिए भी अनेक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन कर रही है। यह संस्था कौशल विकास संबंधी सम्मेलनों आदि में प्रदर्शनियां लगाने और इनमें भागीदारी करने के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। इसने कुशल मानव संसाधनों के विकास के लिए आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी स्थापित किए हैं। इसके द्वार भारत तथा अन्य देशों के लाभार्थियों के लिए हमेशा खुले हैं।

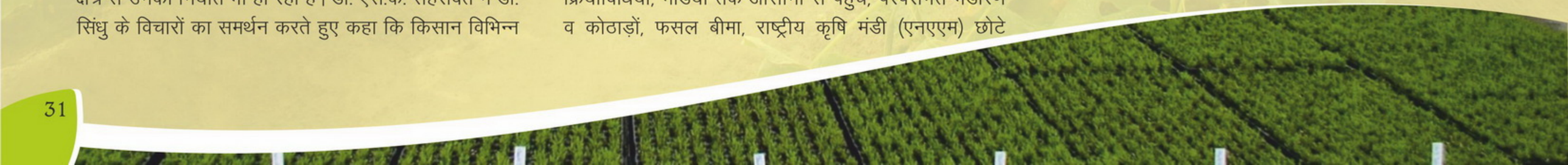

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर
सम्मेलन-2017

किसानों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कृषि में प्राथमिकीकरण

डॉ. अशोक दलवई, आईएस, ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की कृषि के विकास में की गई पहलों तथा सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम चल रहे हैं तथा अनेक आने वाले भी हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि किसानों को आगे बढ़कर सहकारिताएं विकसित करनी चाहिए व मंडियों में अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचना चाहिए ताकि प्रभावी विपणन और निर्यात प्रणाली के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ सके। डॉ. समुंदर सिंह ने फसलों की खेती में खरपतवारों की गंभीर स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये खरपतवार वर्तमान शाकनाशियों के प्रतिरोधी होते जा रहे हैं जो भावी फसलों के लिए एक चुनौती है। गेहूं में *फैलेरिस माइनर* गुल्ली डण्डा /कनकी एक गंभीर समस्या होती जा रही है क्योंकि इसमें शाकनाशी प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार, सरसों और टमाटर की फसलों में परजीवी मरगोजा खरपतवार विशेष रूप से एक नई खरपतवारी समस्या उत्पन्न कर रहा है क्योंकि अब यह नए इलाकों में भी फैल रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन संबंधी प्रयासों की आवश्यकता है। फसल विविधीकरण, फसलों को परिवर्तित करके वैकल्पिक भूमि उपयोग, किस्मों, प्रणाली तथा बुवाई/रोपाई की क्रियाविधि, खरपतवारों के साथ–साथ पोषक तत्वों के प्रबंध, सिंचाई, पादप सुरक्षा के उपायों को शामिल करते हुए नए व क्रमबद्ध तरीके से फसलोत्पादन की आवश्यकता है। डॉ. धर्म सिंह यादव ने सूचित किया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में नई–नई नीतियां ला रही है। सरकार रोपण सामग्री, नई फसलों को अपनाने, बुनियादी ढांचे को स्थापित करने, सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ इस दिशा में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दे रही है। बागवानी में प्रभावी प्रवर्धन के लिए सरकार प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता के नए केन्द्र खोलने जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने करनाल जिले में एक नए राज्य बागवानी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। अधिक शीत गृहों, शीत श्रृंखला प्रदानीकरण प्रणाली, निर्यात केन्द्रों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा विपणन में सुधार हरियाणा सरकार की कार्यनीतिपरक प्राथमिकताएं हैं जिससे किसानों को लाभ होगा और उनकी प्रगति भी होगी। बागवानी के विकास के साथ–साथ किसानों की दशा भी निश्चित रूप से सुधरेगी। डॉ. सोमिन्दर जुनेजा ने हरियाणा में दुग्धोत्पादन में किसानों द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 835 ग्राम हो गई है लेकिन साथ के राज्य पंजाब में यह 973 ग्रा. प्रति व्यक्ति है। हरियाणा सरकार ने गोपशुओं तथा भैंसों के लिए विकासात्मक योजनाएं आरंभ की हैं। देसी हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस के विकास की समेकित स्कीमें राज्य में चल रही हैं। इसके अलावा पशुधन बीमा योजना, खाद्य एवं चारा योजना, राष्ट्रीय पशुधन प्रबंध योजना, कुक्कुट व्यवसाय के लिए पूंजीगत निधि तथा उधार ऋणों के लिए और इसके साथ–साथ अन्य पहलों के लिए सरकार निरंतर सहायता प्रदान कर रही है जिससे राज्य में डेयरी पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। डॉ. ईश्वर सिंह ने मछली बीज की आपूर्ति और नीलामी; तालाबों तथा टैंकों व मछली फार्मों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुदान दिए हैं। राज्य में मछली बीज की नीलामी प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले बृहस्पतिवार को सोनीपत में की जाती है जिसमें किसान अपने लाभ के लिए भाग लेकर स्वयं मूल्य तय कर सकते हैं। सरकार टैंक के लिए 2.4 लाख रुपये, मात्स्यिकी के लिए 10.2 लाख रुपये तथा लवणीय जल वाले क्षेत्रों में जलजंतुपालन के लिए 4.2 लाख रुपये का प्रोत्साहन देती है। यह सहायता विशेष रूप से अनुसूचित जाति के परिवारों को पट्टे पर मछली पालन के लिए उपयुक्त साधन प्राप्त करने के लिए दी जाती है। साथ ही यह मछली पकड़ने व उनकी बिक्री के लिए भी होती है। श्री पी.सी. चौधरी ने नाबार्ड की गतिविधियों तथा कृषि के लिए सामान्य रूप से दिए जाने वाले प्रोत्साहन के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी फार्म उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही नाबार्ड द्वारा फसल बीमा, सुनिश्चित अर्थव्यवस्था, उत्पादक कंपनी निर्माण को बढ़ावा देने, सूक्ष्म सिंचाई पर प्रोत्साहन देने के अलावा कई अनेक अन्य पहलों पर नाबार्ड संबंधित पक्षों को सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड वास्तव में देश के किसानों व कृषक समुदाय के कल्याण व प्रगति में रत है।

2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017
Motivation through Achievers • Peri Urban Farming • A2 Milk : Healthy Milk
Farm to Consumers Directly • Electronic Farm Trading • Organic Farming
18-20 March, 2017 • Suraj Kund, Faridabad, Haryana

1980s
1990s
Synergies
Varieties
X
Fertilizer
X
Irrigation
X
ASSOCHAM

P.C. Chaudhri
Dr. Ashok Dalwai

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मुख्य उपलब्धियां

- ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) – 37 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर जोड़ा गया है, 31 मार्च, 2017 तक 17 और मंडियों के जुड़ने की संभावना है। 01 मार्च 2017 तक 7387.17 करोड़ रुपये मूल्य की 359.34 लाख क्विंटल कृषि उपज e-NAM प्लेटफार्म पर बेची गई है।
- किसान बाजार – पंचकुला में पायलट योजना चल रही है, रोहतक, सोनीपत, करनाल और गुरूग्राम में भी यह शीघ्र ही आरंभ होगी।
- सेब मण्डी, पंचकुला – प्रथम उत्कृष्ट सेब मण्डी कार्यशील है।
- प्लॉट एवं सम्पत्ति प्रबंध प्रणाली – सूचना प्राप्त करने में सरलता हो और इसकी प्रभावी निगरानी के लिए एक ऑन लाइन प्रणाली सृजित की गई है।
- नई मण्डी कार्यरत – कुल 211.39 करोड़ रुपये के व्यय से 22 नई अनाज/सब्जी मंडियां स्थापित की गई हैं।
- विद्यमान मंडियों का उन्नयन – इनके उन्नयन पर कुल 214.34 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
- नए सम्पर्क मार्गों का निर्माण – कुल 232.81 करोड़ रुपये व्यय करके 821 कि. मी. लंबाई के 271 नए सम्पर्क मार्ग स्थापित किए गए हैं।
- सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत – कुल 344.11 करोड़ रुपये के व्यय से 2383 कि.मी. लंबे 827 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य पूरा किया गया।
- मार्गों का जीआईएस मानचित्रण – मार्ग नेटवर्क के लिए एक डेटाबेस सृजित किया गया है। मरम्मत के अंतर्गत आने वाले मार्गों को भू–संदर्भित फोटोग्राफ के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली या जीआईएस पर अंकित किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक तुलाएं – कुल 27.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 26 मंडियों में 140 इलेक्ट्रॉनिक तुलाएं युक्तियां स्थापित करने का कार्य 30.09.2017 तक पूरे होने की संभावना है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

सी–6, सैक्टर 6, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172-2560883, 2561106 फैक्स : 0172-2560197
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : ca.mandiboard@gmail.com
• वेबसाइट : www.hsamb.gov.in • ऑनलाइन मंडी वेब पोर्टल : www.enam.gov.in

मृदा स्वास्थ्य प्रबंध

डॉ. जे.सी. कत्याल, पूर्व कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने सत्र की अध्यक्षता की। इस तकनीकी सत्र में तीन प्रस्तुतीकरण हुए। सत्र का आरंभ डॉ. अनिल राणा, एडीए (एसडब्ल्यूएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' पर दिए गए प्रस्तुतीकरण से हुआ। उन्होंने किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत इस राज्य में वर्ष 2001–02 को की गई थी। वर्ष 2014–15 के अंत तक किसानों को 21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस कार्ड में मिट्टी के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जस्ता, लौह और मैग्नीशियम की स्थिति के बारे में उल्लेख होता है। इस राज्य में 34 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की भी 13 प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 6700 गांवों में से 6250 गांवों के आंकड़े डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 15 फरवरी, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया।

डॉ. वेद फोगट, विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने 'मृदा स्वास्थ्य और इसका प्रबंधन' विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि संसाधनों के कारगर उपयोग के साथ–साथ मिट्टी की दशा या उसके स्वास्थ्य को सुधारकर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जा सकती है। मिट्टी की दशा को मापने के मापदंड हैं : उत्पादकता, पोषक तत्वों की उपयोग की दक्षता, उपज की गुणवत्ता आदि। उन्होंने मृदा के संरक्षण, हरी खाद देने, विविधीकरण, मिट्टी के सुधार और मिट्टी में फसल अपशिष्टों को मिलाने आदि जैसे उपायों पर बल दिया। डॉ. राकेश, सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में जैव उर्वरकों के महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए फसल विशिष्ट जैव उर्वरक विकसित किए गए हैं।

सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉ. जे.सी. कत्याल ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि मृदा भी एक जीवित पदार्थ है। इसलिए इसके स्वास्थ्य का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी व महत्वपूर्ण है। उन्होंने शून्य जुताई पर बल देते हुए मृदा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों और साधनों के बारे में बताया।

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

परिनगरीय खेती

डॉ. एस.के. मल्होत्रा, बागवानी आयुक्त, भारत सरकार ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि भारत को स्वस्थ बनाने की दृष्टि से खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा दोनों का समान महत्व है। योजनाकारों, वैज्ञानिकों तथा किसानों के सम्मिलित गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने खाद्यान्न उत्पादन (271 मिलियन टन) और बागवानी उत्पादों (286 मिलियन टन) का सर्वोच्च उत्पादन 2015–16 में लिया। सब्जियां, फल, डेरी एवं मात्स्यिकी उत्पाद पोषण के मुख्य स्रोत हैं। इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने व इनका उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है और करती आ रही है ताकि लोगों को पोषणिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उत्पादन पर कार्यनीतिपरक ध्यान देने के अलावा मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और विपणन पर सरकार द्वारा अब और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। किसानों द्वारा विशेष रूप से परिनगरीय क्षेत्रों में 'पोषणिक उद्यानों' की स्थापना की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाना है। डॉ. एम.एल. चड्ढा, पूर्व निदेशक, विश्व सब्जी केन्द्र ने कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाएगी। लोगों के परिवर्तित होते हुए भोजन संबंधी स्वभाव तथा पोषण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के कारण तब लोगों की आवश्यकताएं भी भिन्न होंगी। इस परिवर्तन से परिनगरीय क्षेत्र के किसानों को अपनी आय कई गुना बढ़ाने तथा बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में होने वाली मांग को पूरा करने के लिए परिनगरीय खेती में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। जैसे–जैसे क्षेत्र और मांग बढ़ते हैं वैसे–वैसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए कुशल श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी। बागवानी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे बीजोत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, रोपण की विधियां, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता प्रबंधन, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण, विपणन आदि में भी कई गुनी वृद्धि होगी तथा इनके लिए वर्तमान की अपेक्षा कई गुने अधिक कुशल एवं अर्ध कुशल श्रम बल की आवश्यकता होगी।

सुरक्षित खेती, जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक खेती, लम्बवत बागवानी, पोषणिक उद्यानों का विकास, बेमौसमी बागवानी, मेडिकेयर बागवानी, बायो–फोर्टिफाइड फसलों का उत्पादन आदि तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं और इनके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। सुंदर तथा पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त गमलों में पौधा उत्पादन ने उद्योग का रूप ले लिया है और इसमें दिन–ब–दिन विस्तार हो रहा है। अतः उन्होंने नीतिकारों से अनुरोध किया कि वे उभरती हुई मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करें। उन्होंने फसलन प्रणाली में *मोरिंगा* (शहजन) जैसी उच्च मूल्य वाली नई फसलों को शामिल करने का सुझाव दिया। डॉ. अनूप कालरा, डाबर आयुर्वेद इंडिया ने डेयरी गायों के लिए हाइड्रोपोनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से पोषणिक रूप से समृद्ध चारा फसलें उगाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस नई प्रौद्योगिकी से व्हीट ग्रास और मक्का को 8–10 दिनों में बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है तथा डेयरी पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी में 1 कि.ग्रा. चारा उत्पन्न करने के लिए केवल 3 लिटर जल की आवश्यकता होती है जबकि खुले खेत में इतना ही चारा उत्पन्न करने के लिए 80 लिटर जल की जरुरत होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि इस विधि को अपनाकर किसान समय व स्थान की बचत कर सकते हैं और जल की भी बचत करते हुए वांछित मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले चारे का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा धान की रोपाई के लिए नर्सरियां भी तैयार की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक खेती कुछ फसलों तक ही सीमित नहीं है। यह प्रौद्योगिकी अनेक फसलों को विभिन्न क्षेत्रों में उगाये जाने के लिए विस्तारित की जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स के उत्पादन से रोजगार सृजित हो रहे हैं तथा किसानों की आमदनी बढ़ रही है। डॉ. जी.एल. बंसल, हिमाचल प्रदेश ने भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तमिल नाडु सरकार ने हाइड्रोपोनिक खेती के लिए बुनियादी ढांचे की लागत मे अनुदान देना शुरू कर दिया है। गोवा तथा मध्य प्रदेश की सरकारें भी हाइड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं। उनका सुझाव था कि हरियाणा सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए।

श्री तेजभान थरानी, परामर्शक डेरी और पशुधन ने परिनगरीय कृषि में डेरी क्षेत्र के महत्व का व्यापक दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गाय और भैंसों की शुद्ध तथा अच्छी प्रकार से पाली गई देशी नस्लों में अत्यधिक गर्मी व प्रतिकूल दशाओं में भी दूध और मांस उत्पादन की अच्छी क्षमता है। नस्ल शद्धिकरण तथा सुधार कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल 15 प्रतिशत पशु जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण आहार और चारा मिल पाता है। श्रेष्ठ गुणवत्ता के आहार और चारे की उपलब्धता/आपूर्ति तथा स्वच्छता को बनाए रखना ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी एरी के विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हो सकते हैं, अतः इन मुद्दों को सुलझाना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस क्षेत्र को संगठित करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने का सुझाव दिया क्योंकि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और साथ ही श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले दूध व दुग्धोत्पादों का उत्पादन करना भी संभव होगा।

2nd AGRI LEADERSHIP SUMMIT-2017
Motivation through Achievers
A2 Milk : Healthy Milk
Farm to Consumers Directly
Organic Farming
18-20 March, 2017
Haryana
Dr. Parveen Punia
Dr. Madan Chadhha
Dr. S.K. Malhotra
ASSOCHAM

ASSOCHAM

सेमिनार

विषय : परिनगरीय खेती - उभरता हुआ अवसर

नीली क्रांति का विस्तार

अपनी आरंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष डॉ. गोपाल कृष्ण, निदेशक व कुलपति, सीआईएफई ने कहा कि हरियाणा में मछली पालन को एक उच्च क्षमता वाले ऐसे व्यवसाय के रूप में पहचाना गया है जिससे बड़ी मात्रा में स्व रोजगार व आमदनी हो सकती है। इस क्षेत्र से अनेक गौण उद्योगों में भी वृद्धि हो सकती है। मत्स्य आहार से कम लागत पर पशु प्रोटीन उपलब्ध होता है और इस प्रकार मात्स्यिकी व मछली पालन को बढ़ावा देने से पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। मछली पालन हरियाणा में हाल ही में उभरी एक गतिविधि है। तीन दशक से भी कम समय में राज्य में मछली पालन को बहुत महत्व दिया जाने लगा है। हरियाणा प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में प्रति वर्ष औसत मछली उत्पादन 7000 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर है जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत उत्पादन 2900 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर है। दिल्ली के आसपास के जिलों के किसान मछली विपणन की नई तकनीक विकसित करके 600 से 700ग्रा. की मछली पकड़ने में सक्षम हैं और उन्हें जीवित ही दिल्ली के मछली बाजार में ले जा सकते हैं ताकि उन्हें मछलियों का अधिक मूल्य मिले। सभी संसाधनों से राज्य में वर्ष 1966–67 में कुल मछली उत्पादन 600 मीट्रिक टन था जो 2015–16 में बढ़कर अब 121000 मीट्रिक टन हो गया है। सरकार का मुख्य बल उचित प्रशिक्षण देने के साथ–साथ वांछित तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए मछुआरों का एक विशेष वर्ग सृजित करते हुए मछली पालन के अंतर्गत राज्य की सभी उपलब्ध जल कायाओं को इस्तेमाल करना है। राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण तालाबों में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में, भारत में प्रग्रहण दशाओं के अंतर्गत विदेशी तथा देसी शोभाकारी मछलियों की सैकड़ो प्रजातियों का प्रजनन किया जा रहा है। उत्पादन का अधिकांश भाग घरेलू मंडियों में ही खप जाता है और कुछ भाग ही निर्यात हो पाता है। अधिकांश विदेशी प्रजातियां प्रजनित करके आसानी से पाली जा सकती हैं क्योंकि इसके लिए विकसित प्रौद्योगिकी बहुत सरल तथा आसान है। हरियाणा के किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पालन को एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं।

श्री हरि कृष्ण ने बताया कि इस क्षेत्र का सकल जीडीपी में लगभग 1 प्रतिशत और कृषि जीडीपी में 4.6 प्रतिशत योगदान है। ऐसा आकलन है कि वर्ष 2030 तक कुल मछली उत्पादन में जलजंतुपालन का हिस्सा बढ़कर 62 प्रतिशत हो जाएगा। जलजंतुओं की मांग न केवल मात्रा के आधार पर होगी बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और विविधता के अनुसार भी होगी। ऐसा संसाधन उपयोग की दक्षता में सुधार करते हुए विस्तार व गहनीकरण के माध्यम से दिया जा सकता है जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र अब परंपरागत प्रणाली से हटकर आधुनिक प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है जिसमें और अधिक यंत्रीकृत, गहन व आधुनिक उत्पादन व प्रसंस्करण प्रणालियां शामिल हैं। हरियाणा में लवणीय जल में मछली पालन की उच्च क्षमता प्रदर्शित हुई है। सीआईएफई, रोहतक में इस मामले में सफलता की कहानी लिखी है और भारत में न केवल केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं बल्कि मछली और झींगा पालन के लिए अंतःस्थलीय लवणीय मृदाओं व भूजल के उपयोग पर समर्पित अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में और अधिक प्रचार–प्रसार की क्षमता है। जिससे अंतःस्थलीय राज्यों में मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर नील क्रांति लाई जा सकेगी।

डॉ. जी. राठौर और डॉ. एन. सूद ने मछली पालन पर आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर बल दिया। यह बताया गया कि मछलियों के आहार और उनके पालन, प्रजनन तथा जीरा

उत्पादन के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान होने के अतिरिक्त मछली पालकों को मछलियों के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मछलियों के रोगों की पहचान की गई है और उनके प्रबंध की विधियां भी मानकीकृत की जा चुकी हैं। किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें रोग प्रबंध की विधियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा देश में नीली क्रांति के मामले में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मछलियों की औसत उत्पादकता प्रति हैक्टर 2,900 कि.ग्रा. है जबकि हरियाणा में यह 7,200 कि.ग्रा. है। इस प्रकार, हरियाणा प्रति हैक्टर मछली उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।

हरियाणा में मछली उत्पादकों को सहायता देने के लिए विभाग ने फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर, प्रत्येक स्थान पर एक–एक और इस प्रकार तीन मछली बाजार स्थापित किए हैं। राज्य में विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गुरूग्राम में दो और नई मछली मंडियां स्थापित की जाएंगी। डॉ. सालिम सुल्तान, वरिष्ठ परामर्शक, भारत सरकार ने मछली उत्पादन को दुगुना करने के उद्देश्य से नीली क्रांति तथा पुनः परिचारणशील जलजंतुपालन प्रणाली के बारे में बताया।

मछली पालन विभाग

मुख्य उपलब्धियां

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां	वर्ष 2016–17 का लक्ष्य	वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां
1.	मछली पालन के अंतर्गत क्षेत्र	17800.00 हैक्टर	18400.00 हैक्टर	18975.00 हैक्टर
2.	स्टॉक किया गया मछली जरा	6400.00 लाख	7600.00 लाख	7900.00 लाख
3.	मछली उत्पादन	121000.00 मीट्रिक टन	142800.00 मीट्रिक टन	142200.00 मीट्रिक टन
4.	उत्पन्न मछली जीरा	1069.00 लाख	1375.00 लाख	1190.36 लाख

- हरियाणा का प्रति वर्ष प्रति हैक्टर क्षेत्र में अंतः स्थलीय मछली उत्पादकता के मामले में देश में दूसरा स्थान है। यह उत्पादकता 7200 कि.ग्रा./हैक्टर/वर्ष है जिसे 2017–18 के अंत तक बढ़ाकर 10000 कि.ग्रा./हैक्टर/वर्ष किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा मछली पालन में रोगमुक्त राज्य घोषित किया गया है।
- विभाग ने नीली क्रांति : मात्स्यिकी का समेकित विकास और प्रबंधन पर केन्द्रीय सैक्टर की स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।
- हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां श्वेत झींगा *लैप्टोपेनियस वेन्नामेई* के पालन के लिए परिसीमित भूमि में अंतःस्थलीय लवणीय जल का उपयोग किया है।
- शासकीय मछली जीरा फार्म, झज्जर में स्थित हाई–टेक तथा अल्ट्रा मॉडर्न शोभाकारी मछली स्फुटनशाला सरकार द्वारा अनुमोदित देश की एकमात्र परियोजना है।
- कुल 28 हैक्टर लवण प्रभावित क्षेत्र में सफेद झींगा पालन के लिए किए गए सफल परीक्षणों के पश्चात् विभाग ने सफेद झींगा पालन के अंतर्गत 39.64 हैक्टर क्षेत्र को और शामिल किया है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान मछली पालन के लिए 29.24 हैक्टर जल भराव वाले क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसानों को निवेश की प्रति इकाई पर झींगा पालन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराती है।
- मछली पालन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान तथा कुशलता के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में एक प्रशिक्षण उप केन्द्र स्थापित किया गया है।
- विभाग ने पेंगासियस सूची मछली पालन के लिए स्वर्ण ज्यंती वर्ष के अंतर्गत भारत सरकार को 1262.00 लाख राशि का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मछली पालन विभाग

बेज़ 31–32, सैक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172-2565743, 2566081 फैक्स : 0172-2560197
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : fisheries.haryana@gmail.com
• वेबसाइट : www.harfish.gov.in

सेमिनार

विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार

जल–संसाधनों का प्रबंधन

अपनी आरंभिक टिप्पणी में डॉ. ए.के. गोयल, पूर्व अधिष्ठाता, सीओएई और टी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने जल और इसकी उपलब्धता के महत्व का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2 प्रतिशत है जबकि भारत के पास विश्व के कुल जल संसाधनों का 4 प्रतिशत भाग उपलब्ध हैं। हम अपने जल के लगभग 80 प्रतिशत भाग का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य से करते हैं जबकि विश्व में कुल मिलाकर 69 प्रतिशत जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। श्री एस. मखीजा, स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, जलगांव ने जल संभर विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों द्वारा वर्षा जल के संग्रहण व उसके भंडारण पर बल देते हुए कहा कि किसानों को सर्वोच्च जल उपयोग दक्षता प्रणाली जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ड्रिप सिंचाई के विशेष संदर्भ में सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताया।

डॉ. राजपूत, पूर्व प्राध्यापक, भा.कृ.अ.सं., पूसा, नई दिल्ली ने भी जलसंभर विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जलसंभर विकास के महत्व के बारे में बताया। डॉ. राजपूत ने कहा कि हम जितना भी जल एकत्र करते हैं उसका लगभग 50 प्रतिशत भाग नाली प्रणाली द्वारा नष्ट हो जाता है, अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जल संसाधनों के उचित विकास व उनके वैज्ञानिक उपयोग पर विशेष बल दिया। देश में उपलब्ध दुर्लभ जल संसाधनों के उचित उपयोग के लिए भूमि को उचित रूप से समतल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सिंचाई जल के उपयुक्ततम उपयोग के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से देश के अधिक से अधिक क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रमुख बातों व इसके महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया।

डॉ. नीलम पटेल, वैज्ञानिक, परिशुद्ध फार्मिंग विकास केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ने अपना प्रस्तुतीकरण 'प्रति बूंद अधिक फसल – प्रत्येक बूंद का उपयोग करना' नारे के साथ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के लिए योजना बनाते समय किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या उत्पन्न करना है, कब उत्पन्न करना है और कम से कम लागत से अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अंततः किस प्रकार से कार्य करना है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जल तथा मृदा संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अब हमें घटते हुए जल संसाधनों और इसकी बढ़ती हुई मांग की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भूमि के समतलीकरण, जल कायाओं की सफाई, अपेक्षाकृत घटिया गुणवत्ता वाले जल को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले जल के साथ उचित मात्रा में मिलाकर उपयोग करने का आह्वान किया। जल के उपयुक्ततम उपयोग में ड्रिप सिंचाई के महत्व पर चर्चा की गई। उनका कहना था कि कभी–कभी किसान सौर प्रणाली की दक्षता पर सवाल करते हैं। उनका मानना था कि सौर प्रणाली में कोई समस्या नहीं है लेकिन इसकी दक्षता जल के संसाधनों जैसे तालाब / नलकूप व जल की गहराई के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती है।

सेमिनार

विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

डॉ. के.पी. सिंह, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने सत्र की अध्यक्षता की। अपनी आरंभिक टिप्पणी में उन्होंने विकसित देशों में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन कार्यनीतियों का अध्ययन करने और उनमें उचित सुधार के पश्चात् अपने देश की दशाओं के अंतर्गत लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाने की आवश्यकता की रूपरेखा प्रस्तुत की, ताकि कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की ओर शहरियों का ध्यान आकृष्ट हो और उन्हें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर समझ हो सके।

इसके पश्चात् वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यूके और स्पेन से प्रस्तुत किए जाने वाले सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा करने के प्रयास किए गए लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह सफल न हो सका। तथापि, श्री डैन आलुफ, एग्रीकल्चरल काउंसलर, इज़राइल और श्री आनंद कृष्ण, डिप्टी काउंसलर, नीदरलैंड ने, जो सत्र में उपस्थित थे, अपने पत्र प्रस्तुत किए। श्री अलुफ ने राज्य में भारत–इज़राइल कार्यक्रम के द्वारा चलाए जा रहे सहयोगी प्रयासों के प्रभाव पर प्रकाश डाला और रूचि के क्षेत्रों को और विस्तृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कृष्णन ने नीदरलैंड सरकार और एलयूवीएएस के बीच कम दूध देने वाली देसी गायों के संकर प्रजनन के माध्यम से दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किए गए समझौता ज्ञापन के विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया।

कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार थे :

1. यह सम्मेलन दो दिन का होना चाहिए। एक पूरा दिन सरकारी एजेंसियों के लिए रखा जाना चाहिए जिसमें वे किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराएं।

2. दूसरा दिन कृषि नेताओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि विषय में रूचि लेने वाले प्रेरित किसान अपनी रूचि के क्षेत्रों के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त कर सकें।

विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार

टिकाऊ फसलोत्पादन के लिए संरक्षण कृषि– जलवायु अनुकूल कृषि और जोखिम प्रबंधन

डॉ. आर.के. यादव, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग ने सत्र की अध्यक्षता की। सत्र में यह बताया गया कि विश्व उपग्रह छायाओं से फसलों के उत्पादन परिदृश्य पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों को परिलक्षित किया गया है जहां दक्षिण एशिया इस मामले में हॉट स्पॉट के रूप में चिह्नित है। भारत तथा हरियाणा में जलवायु में परिवर्तन का कारण फसल अपशिष्टों और विशेष रूप से चावल और गेहूं की फसलों के कचरे का कुप्रबंध है जो उपग्रही छायाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फसलों के कचरे को जलाने के परिणामस्वरूप जैविक कार्बन तथा मिट्टी में मौजूद प्राणियों और वनस्पतियों के संदर्भ में मिट्टी की हालत खराब हुई है। बढ़े हुए मृदा और वातावरणीय तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल पुनर्भरण में कमी और फसलों द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग फसलों की उपज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। फसलों के कचरे को जलाने का यह कार्य तत्काल बंद होना चाहिए और इसकी बजाय इस कचरे को खेत में ही मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रहे। उत्पादन पर प्रतिकूल जलवायु का प्रभाव कम करने, उत्पादन की लागत घटाने, उचित संसाधन प्रबंध करने, जैव–फोर्टिफिकेशन और जलवायु सूचना संबंधी सेवाओं को जलवायु के लिए अनुकूल कृषि को अपनाने की प्रक्रिया में अपनाना होगा। इसलिए संरक्षण कृषि में अंतरफसलों, रिले फसलों, जुड़वां कतारों में रोपाई करते हुए फलीदार फसलों को शामिल करना होगा, ताकि उपयुक्त स्थान, पोषक तत्वों, सिंचाई का उपयोग करते हुए बेहतर प्रोटीन से युक्त खाद्योत्पादन किया जा सके। इसके साथ ही गेहूं–चावल, गेहूं–कपास/मक्का फार्मिंग प्रणालियों में फसल पकने की अवस्था पर उच्च तापमान को सह सकने वाली किस्मों का विकास किया जाना चाहिए।

जैविक व अजैविक प्रतिकूल स्थितियों को न्यूनतम करने के लिए रोपाई की उचित क्रियाविधि, जल और पोषक तत्वों का सटीक प्रबंधन और इसके साथ–साथ फसलों की स्थान विशिष्ट व जलवायु की दृष्टि से

अनुकूल किस्मों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकियों में से फसल अपशिष्ट को मिलाने के लिए रोटावेटर के उपयोग का फसलों की उपज पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है क्योंकि मृदा की परत के दब जाने से मृदा की केशिकाएं या कैपिलरी छोटी हो जाती हैं, जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और पोषक तत्वों का उपयोग कम हो पाता है तथा फसल उपज में कमी आ जाती है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्मार्ट व्यापार माडल और ऐसी स्मार्ट तकनीकें विकसित करने का सुझाव दिया गया जिनसे उत्पादन लागत कम हो सके। इनमें से कुछ तकनीकें हैं हैप्पी सीडर, सीधी रोपाई और शून्य जुताई आदि। फसलोत्पादन के लिए जैविक उर्वरक के रूप में जैवोत्पाद के साथ–साथ जैव ईंधन के रूप में उपयोग के लिए बायोगैस सृजित करने के लिए सभी घरेलू तथा डेयरी मवेशियों के उपयोग की आवश्यकता है। इसी प्रकार, खेत की मिट्टी में मिलाए गए फसल अपशिष्ट सूक्ष्मजीवों के माध्यम से कार्बनिक पोषक तत्वों में बदल जाते हैं और तब फसल के पौधे उनका बेहतर उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार, नई उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जैव मात्रा के संरक्षण व किफायती इस्तेमाल की और अधिक जरूरत है।

राज्य तथा भारत सरकार की फसल बीमा नीतियां भी प्रभावित किसानों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं। बीमा संबंधी प्रीमियम, बीमे के अंतर्गत आने वाली फसलों के प्रकार, फसलों को होने वाली हानि के मूल्यांकन के आधार की श्रेणियों तथा फसल को होने वाली क्षति के लिए किससे और कहां सम्पर्क किया जाए, शिकायतें कहां दर्ज की जाएं और उनका निपटारा कहां और कैसे हो, इसके बारे में किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए। किसानों को नियमित रूप से फसल बीमा कराने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे फसलों को प्रकृति से होने वाली हानि से बचा सकें और अपने फार्मिंग व्यवसाय को कम से कम निराशाजनक स्थिति से निकाल सकें। राज्य में परिनगरीय बागवानी के लिए विस्तार कार्यनीतियों और विद्यमान विस्तार प्रणाली को सबल बनाया जाना चाहिए। हरियाणा में फलों, सब्जियों तथा पुष्पों जैसे बागवानी उत्पादों की बिक्री के लिए अपार अवसर हैं क्योंकि ये राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निकट हैं और यहां की मंडियों में इन सभी की बहुत मांग है। फार्म उपज से बेहतर लाभ लेने के लिए किसानों को उत्पादक कंपनियां गठित करने का परामर्श दिया जाना चाहिए और उन्हें अपनी उपज की सामूहिक बिक्री करनी चाहिए। इस प्रकार के नए दृष्टिकोणों से राज्य के किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा और इस प्रक्रिया में बिचौलियों व दलालों की भूमिका भी समाप्त हो जाएगी।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हेफेड)

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

मुख्य उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2015–16 के लिए व्यापार टर्न ओवर तथा लाभ क्रमशः 8780.11 करोड़ रुपये और 38.60 करोड़ रुपये (कर अदा करने के पश्चात्) थे।
- कुल 18.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीफ मौसम में खरीद की गई जो अब तक की सर्वाधिक है। केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई को 99.97 प्रतिशत कस्टम मिलीकृत चावल (सीएमआर) उपलब्ध कराया गया।
- मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के अंतर्गत हरियाणा में पहली बार मूंग की खरीद की गई है। हेफेड ने इस मौसम में हिसार और सिवानी (भिवानी) में 16,932 क्विंटल मूंग की खरीद की है।
- हेफेड ने राज्य में कुल बेचे गए बाजरा में से 22 प्रतिशत बाजरे की खरीद की है।
- रबी 2016 मौसम के दौरान हेफेड ने 25.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। यह राज्य की सभी खरीद एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल खरीद का 37 प्रतिशत है।
- राज्य के किसानों को सहायता देने के लिए हेफेड ने रबी 2016 के दौरान सूरजमुखी के 4,785 मीट्रिक टन बीज की खरीद की है।
- दिनांक 01.04.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान हेफेड ने 0.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी बेचा है। दिनांक 01.01.2017 तक हेफेड के पास 0.27 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.45 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध था।
- हेफेड सुगर मिल असंध ने वर्ष 2015–16 के पिराई मौसम के दौरान गन्ने से 11 प्रतिशत चीनी प्राप्त की है जो अब तक की सर्वाधिक मात्रा है।
- दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान हेफेड ने 54.02 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पाद बेचे हैं।
- हेफेड ने अब राज्य सरकार का नया ई–निविदा पोर्टल (www.haryanaeprocurement.gov.in) अपनाया है। निर्माण कार्यों तथा कुछ और कार्यों के लिए ई–निविदा नए पोर्टल पर आरंभ की जा चुकी है, ताकि निविदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आईटी शासन संबंधी पहलें 'ऑनलाइन सीएम विंडोस' तथा 'ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस' को हेफेड द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हेफेड)

Synonymous with Quality, Purity & Excellence

An ISO 9001:2000 Organization

hafed

Hafed Consumer Products

सैक्टर 5, पंचकूला, हरियाणा. • दूरभाष : 0172.2590518, 2590709

• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : hfdmd@hry.nic.in

• वेबसाइट : www.hafedhry.nic.in

सेमिनार

विषय : जोखिम प्रबंधन, जलवायु के अनुकूल कृषि तथा इलेक्ट्रॉनिक फार्म व्यापार

सीधी बिक्री और इलेक्ट्रॉनिक बाजार

डॉ. अभिलक्ष लेखी, आईएएस, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने सत्र की अध्यक्षता की। अपनी आरंभिक टिप्पणी में डॉ. लेखी ने बताया कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके एक अंग के रूप में सीधे विपणन या बाजार में माल को खुद ले जाने की विधि को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मंडियों में किसानों के हितों की रक्षा हो सके। कृषि उत्पादों का विपणन परंपरागत विधि की बजाय अब ई–विपणन द्वारा हो रहा है जिससे किसान उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच रहे हैं। अब यह खेती संबंधी कार्यों में मूल्य वर्धन के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो रहा है। फार्म उत्पादों के सीधे विपणन में एक महत्वपूर्ण तत्व किसान द्वारा अपनी उपज का मूल्य स्वयं तय करना है। इससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को मंडियों का अध्ययन करने तथा अपनी पसंद पर उत्पादों को बेचने के अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि किसान और ग्रामीण युवाओं को ई–नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि विपणन) से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे इसके लाभ प्राप्त कर सकें। ई–नाम किसानों को अपनी पसंद की किसी भी मंडी में इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। इसके लिए देश की थोक मंडियों को कम्प्यूटरीकृत करना होगा और उन्हें एक–दूसरे से जोड़ना होगा। अब तक हरियाणा में 37 मंडियां परस्पर जोड़ी जा चुकी हैं और 50 अन्य मंडियां भी शीघ्र ही जोड़ दी जाएंगी। राज्य की सभी 108 मंडियों का देश की कुल 568 थोक मंडियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सम्पर्क हो जाएगा।

डॉ. जे. गणेसन, आईएएस, सीए, एचएसएएमबी का विचार था कि अब तक 11 राज्य ई–नाम के अंग बन चुके हैं और शीघ्र ही अन्य राज्यों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। हरियाणा मंडियों के कम्प्यूटरीकरण के मामले में देश के अन्य राज्यों से आगे है और यहां इन मंडियों को ई–नाम का अंग बना लिया गया है। उपज की गुणवत्ता की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां लगाई जा रही हैं। हरियाणा ने किसानों तथा ग्रामीण युवाओं के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे इस प्रणाली का लाभ उठा सकें। कृषि विपणन संबंधी कानून आसान बनाए गए हैं। देश की किसी भी मंडी

में ई–नाम के माध्यम से उत्पादों की बिक्री व खरीद के लिए केवल एक लाइसेंस लेना होगा। खरीद, भंडारण, वितरण संबंधी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। फूडनेट तथा ई–नाम को एकीकृत किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य लेने में सहायता मिलेगी और पहले बिचौलियों द्वारा जो उनका शोषण होता था, उससे भी बचा जा सकेगा। अब तक राज्य में ई–नाम के अंतर्गत 6 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है। राज्य में कृषि–मॉल स्थापित किए गए हैं, पंचकुला में किसान बाजार खोला गया है। इसी प्रकार के बाजार राज्य के विभिन्न जिलों में खोले जाएंगे। ऐसे बाजारों में किसानों द्वारा स्थान का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क या किराया नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तुलाएं या तराजू किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस अवसर पर 'उत्तम फसल, उत्तम दाम' शीर्षक की ई–नाम पर एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई।

डॉ. जे.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ने कहा कि कृषि को नया स्वरूप देने में सहायता करने के लिए नवोन्मेषी किसानों को कृषि प्राध्यापक नियुक्त करने की एक नई पहल शुरू की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को और अधिक लाभदायक बनाने में सहायता मिलेगी। किसानों की सोच को विविधीकृत कृषि की दिशा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। किसान परंपरागत कृषि से वाणिज्यिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को श्रेणीकरण, ब्रांडकरण, पैकेजिंग तथा ई–नाम के महत्व से अवगत कराया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड के एक किसान हरप्रीत सिंह ने किसानों को सुझाव दिया कि वे स्वयं को उपभोक्ता मंडियों से जोड़ें और विश्वसनीय नियमित आपूर्तिकर्ता बनें। वे स्वयं सब्जियों तथा डेरी उत्पादों को होटलों में आपूर्त करते हैं और प्रति एकड़ औसतन 35000/–रु. का शुद्ध लाभ कमाते हैं।

ई–नाम के दुष्यंत त्यागी ने बताया कि मंडियां कम्प्यूटरीकृत की जा रही हैं तथा 'एक देश एक बाजार' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें परस्पर जोड़ा जा रहा है। विपणन प्रणाली की पारदर्शिता, सूचना के साथ जुड़ाव और बिक्री की स्वतंत्रता ई–नाम के मुख्य लक्ष्य हैं। उन्होंने बताया कि देश की 568 थोक मंडियों में से 421 को परस्पर जोड़ा जाएगा और ये ई–नाम के अंतर्गत कार्य करना शुरू कर देंगीं। लगभग 34 लाख किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 6.5 लाख हरियाणा के किसान हैं। इनके अलावा 78 हजार व्यापारियों को भी पंजीकृत किया जा चुका है। पिछले 4 महीनों के दौरान ई–नाम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 13958 करोड़ रुपये का टर्न–ओवर हुआ है। यह बताना उल्लेखनीय है कि ई–नाम के माध्यम से होने वाले कुल टर्न –ओवर में से 50 प्रतिशत का टर्न–ओवर हरियाणा के किसानों की भागीदारी के कारण संभव हुआ। उन्होंने ई–नाम की कार्य प्रणाली पर एक फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ई–नाम पोर्टल पारस्परिक क्रियाशील है और इस प्रकार स्टेकहोल्डर इस पर अपने विचार रखते हुए आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। डॉ. प्रतिवा आनंद ने बागवानी में सीधे विपणन के बारे में बताया। यह बताया गया कि पुष्पों, घरों में फूलों के गमले रखने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, फूलों से तेल निकालने, शुष्क फूलों, फूलों के बीज आदि के लिए घरेलू तथा वैश्विक बाजारों में व्यापार के बहुत अवसर उपलब्ध हैं। डॉ. बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान ने किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बाजारोन्मुख कृषि की दिशा में बढ़ने का परामर्श दिया क्योंकि इससे निवेश पर बेहतर लाभ लेने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेती की अच्छी विधियां अपनाने से खेती की लागत कम करने, संसाधनों की दक्षता बढ़ाने और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

कृषि प्रचालन तंत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण – हरियाणा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र

श्री आर.के. सिंह, प्रबंधक व्यापार, एचएससीडब्ल्यू ने सत्र की अध्यक्षता की। इस तकनीकी सत्र में तीन औपचारिक प्रस्तुतीकरण हुए। पहला प्रस्तुतीकरण श्री करम चेची, अनुसंधान निदेशक, तकनीकी विज्ञान अनुसंधान, नोएडा ने 'बाजार पहुंच प्रणाली – शीत श्रृंखला में एक नई संकल्पना' विषय पर प्रस्तुत किया। श्री चेची ने अपना प्रस्तुतीकरण भंडारागार की संख्या और क्षमता के संदर्भ में देश में शीत भंडारगृहों की स्थिति पर चर्चा करते हुए आरंभ किया। उन्होंने कहा कि भंडारों के स्वामित्व के वितरण के आधार पर देश में बहुत भिन्नता है। केवल 2 प्रतिशत शीत भंडार गृह ही निजी फर्मों के स्वामित्व में हैं और 2 प्रतिशत सहकारिताओं के स्वामित्व में हैं। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि हरियाणा में अधिक से अधिक बहूद्देशीय शीत भंडारण सुविधाएं विकसित की जाएं। हरियाणा में केवल 318 शीत गृह हैं जो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने बाजार पहुंच प्रणाली के विकास के लिए सरकारी पहल और सहायता की आवश्यकता पर बल दिया और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं : पैकेजिंग, भंडारण, प्रशीतलन और परिवहन। इन सबके लिए विभिन्न प्रकार की प्रशीतलन परिवहन सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए।

दूसरा प्रस्तुतीकरण श्री पंकज भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड, मुम्बई ने 'कृषि प्रचालन तंत्र में उभरती प्रवृत्तियां, द्विपक्षीय प्रबंधन और निधिकरण की सुविधाएं' विषय पर दिया। उनका मुख्य नारा था 'फीडबैक वहां दें जहां उसकी आवश्यकता हो और जहां उसका कोई लाभ हो'। उन्होंने कहा कि देश में सशक्त प्रचालन तंत्र के बहुत अवसर हैं। भारत में भंडारगृहों का अभी व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र के समक्ष देश में भंडारण क्षेत्र के मामले में बड़े अवसर उपलब्ध हैं। भंडारागार सुविधाओं के मामले में सरकार का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भंडारण संबंधी अनेक संरचनाएं बिना मानकों और मानदंडों को अपनाए बनाई गई हैं जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में उचित भावी कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। अपर्याप्त मूल्य निर्धारण प्रणाली, मंडियों तक सीमित पहुंच, अनेक बिचौलियों का होना भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त न होना, भंडारण का असमान वितरण व द्विपक्षीय सम्पर्क की कमी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनपर विचार किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सार्वजनिक–निजी साझेदारी का सुझाव दिया गया। श्री विजय सरदाना ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

ASSOCHAM
2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

मुख्य उपलब्धियां

- एचएसडब्ल्यूसी 31.01.2017 तक 78 प्रतिशत उपयोग के साथ 112 वेयरहाउस नेटवर्क के माध्यम से 17.26 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता से युक्त है और भंडारण की साज–संभाल कर रहा है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान 91,304 क्षमता के गोदाम निर्मित करने का प्रस्ताव है।
- एचएसडब्ल्यूसी ने 2016–17 के दौरान 11.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है जो एचएसडब्ल्यूसी के इतिहास में सर्वोच्च है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान एचएसडब्ल्यूसी के स्टाफ ने 518 गांवों में 6335 किसानों को वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण की विभिन्न विधियों व लाभों के बारे में शिक्षित किया (31.01.2017 तक)।
- एचएसडब्ल्यूसी ने अपने परिसरों/गोदामों में किसानों/व्यापारियों आदि के स्टॉक के लिए विसंदूषण की सेवाएं उपलब्ध कराकर 9.79 लाख किसानों को सेवाएं प्रदान की हैं।
- एचएसडब्ल्यूसी ने वर्ष 2015–16 के दौरान 23.45 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

बेज़ 15–18, सैक्टर 2, पंचकूला, हरियाणा • दूरभाष : 0172–2578829.31 फैक्स : 0172–2578481
• किसान काल सेंटर 1800 180 1551 • ईमेल : hwc@hry.nic.in • वेबसाइट : www.hwc.nic.in

किसानों की आमदनी दुगुनी करना

हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं जो इस प्रकार हैं :

क. फसल विविधीकरण और परिनगरीय खेती द्वारा कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि :

- कृषि में उच्च मूल्य वाली फसलों में वार्षिक वृद्धि इस प्रकार है : कपास में 14.1% , गन्ना में 2%, फलों में 4. 2%, सब्जियों में 5.7%, पशुपालन में 3.5% और मछली पालन में 12% का लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया गया है।
- कृषि : रेशा फसलों नामतः कपास में 0.274 मीट्रिक टन/हैक्टर से 0.693 मीट्रिक टन हैक्टर तथा गन्ना में 75.18 मी.टन/हैक्टर से 86.30 मी.टन/है. उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- बागवानी : बागवानी में उत्पादकता को फलों के मामले में 16.54 मी.टन/है. से 22.00 मी.टन/है. व सब्जियों में 14.99 मी.टन/है. से 22.00 मी.टन/है. लक्ष्य रखा गया है। सब्जियों की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर 11 प्रतिशत बढ़ाकर इसे वर्तमान के 70.24 लाख मी.टन से 2022 तक 138.23 लाख मी.टन करते हुए दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में पहला बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है।
- पशुधन : दुग्धोत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ इसका सकल उत्पादन 83.81 लाख टन से बढ़ाकर 112.00 लाख टन करने का लक्ष्य है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को 2022 तक 835 ग्रा. से बढ़ाकर 1050 ग्राम करने के लिए गोपशुओं की देसी नस्ल के परिरक्षण और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- मात्स्यिकी : मत्स्य उत्पादकता के मामले में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। इसका लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को 1.21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2022 तक 8.23 लाख मी.टन और मत्स्य उत्पादकता को 6.8 मी.टन से 15.0 मी.टन प्रति वर्ष प्रति हैक्टर करना है। इसी अवधि में मछली जीरा उत्पादन को 6400 लाख से बढ़ाकर 21800 लाख करने व क्षेत्र को 17,800 से बढ़ाकर 54,500 हैक्टर करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। हरियाणा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में रोगमुक्त राज्य घोषित किया गया है और यह देश का पहला ऐसा राज्य है जहां लवणीय जल में अंतरदेशीय झींगा पालन को सफलतापूर्वक अपनाया गया है।
- हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ावा देने तथा 71 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से संगठित विपणन के लिए 510 करोड़ रुपये के निवेश का फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम आरंभ किया है।

ख. सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग के संसाधन

- स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, भूमिगत पाइप लाईन (यूजीपीएल) तथा जल संभर परियोजनाओं के माध्यम से आवश्यकता से अधिक दोहित, नाजुक तथा अर्ध नाजुक विकास ब्लॉकों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए 36 ब्लॉकों की पहचान की गई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र को 20–22 तक 6.9 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 9.50 लाख हैक्टर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रकार कृषि क्षेत्र में 26.57 प्रतिशत के अनुसार वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

ग. संसाधन उपयोग की दक्षता

- उर्वरकों के अनावश्यक उपयोग से बचाने के लिए अब तक 15.73 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जा चुके हैं तथा प्रभावी विस्तार संबंधी गतिविधियों से

- खरीफ 2016 में यूरिया की खपत को 10 प्रतिशत तथा रबी 2016–17 में पिछले मौसम की तुलना में 6 प्रतिशत कम किया गया है। इस संदर्भ में प्रमाणिक जैविक खेती को गौशालाओं से जोड़ा गया है तथा राज्य के 11 जिलों के 20 विकास ब्लॉकों के क्लस्टर को चुना गया है।
- जलवायु स्मार्ट कृषि से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए हरियाणा में 250 जलवायु स्मार्ट ग्राम विकसित करने के लिए 22 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना शुरू की गई है।

घ. एपीएमसी अधिनियम में सुधार के द्वारा विपणन क्षेत्र में सुधार

- कुल 8000 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर से राज्य की 54 मंडियों में ई–नाम पोर्टल के माध्यम से ई–व्यापार आरंभ किया गया है।
- एकल व्यापार लाइसेंस के अंतर्गत अप्रतिबंधित व्यापार को अनुमति दी गई है तथा बाजार शुल्क में भी एक ही उगाही लेने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
- कृषक उत्पादक संगठनों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए लाइसेंस से छूट दी गई है।

- किसान मंडियों को राज्य की विभिन्न मंडियों में स्थापित किया जा रहा है।
- ठेके पर खेती की अनुमति दी गई है और राज्य में इसे उदार बनाया जा रहा है।

ड. जोखिम प्रबंधन

- खरीफ 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

(पीएमएफबीआई) लागू की जा रही है और इस सकीम के तहत 85 प्रतिशत सकल फसल क्षेत्र है और विभिन्न कृषि फसलों, नामतः गेहूं, धान, कपास, सरसों, बाजरा, मक्का, जौ और चना के अंतर्गत सकल फसलित क्षेत्र के 95 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को लाया गया है।

च. कृषि में कुशलताएं

- हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने व पुरस्कृत करने के लिए 18 से 20 मार्च, 2017 तक फरीदाबाद में दूसरे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें एक लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया।
- सरकार ने 17 फरवरी, 2017 को एनएसडीसी के अंतर्गत भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा कृषि/बागवानी के क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट कुशलताएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आठ केन्द्रों की पहचान की।

छ. अनुसंधान एवं विकास

- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने अनेक ऐसी श्रेष्ठ किस्में जारी की हैं जिनमें गेहूं की 30 प्रतिशत, मक्का की 65 प्रतिशत, बाजरा की 45 प्रतिशत और चने की 108 प्रतिशत उत्पादकता बढ़ाने की संभावना है।
- विश्वविद्यालय ने गेहूं के लिए शून्य जुताई द्वारा बुवाई, चावल के लिए सीधी बीजाई व मिट्टी परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों के प्रबंधन की सिफारिश की है। इसने समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल तथा गाय पर केन्द्रित आईएफएस मॉडल भी विकसित किया है जिसमें किसानों की आमदनी 2,21,199/रु./हैक्टर बढ़ाने की क्षमता है।

सूरजकुण्ड, फरीदाबाद में आयोजित द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में बी2जी/जी2जी परिचर्चाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

क.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम	पता	उत्पाद/सेवाओं की प्रकृति	सम्पर्क सूत्र	ई–मेल आईडी
1.	सुश्री टेरेसा बेरेस	कृषि, मात्स्यिकी, खाद्य एवं पर्यावरण काउंसलर	स्पेन दूतावास	12, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली–110011	सरकारी	981011330	tbarres@magrama.es.
2.	सुश्री राशा ओमार	देश प्रतिनिधि	इंटरनेशनल फंड फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी, यूएन एजेंसी)	2, पूर्वी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली	ऋण तथा अनुदान – राज्य सरकरों को	9811990167	r.omar@ifad.org
3.	श्री नाहोट जे. सिम्बलोन	मिनिस्टर काउंसलर	इंडोनेशिया गणराज्य दूतावास	50ए, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली	सरकारी	9582210239	nahotjohn@yahoo.com
4.	श्री पंकज नवानी	सीईओ	बिंसार फार्मस	ग्राम जंती खुर्द, निकट कुंडली एरिया, सोनीपत	मिल्क फार्म फ्रेश	9811896764	pankar.navani@gmail.com
5.	श्री जय कुमार गुप्ता,	महाप्रबंधक	टिल्डा हैन प्राइवेट लिमिटैड	कारपोरेट हाउस, प्लॉट नं03, इफको भवन, छठा तल, सैक्टर–32, गुड़गांव	जैविक उत्पाद एवं चावल	9717700150	jai@tilda.com
6.	श्री हरदीप सिंह काला	संयंत्र प्रबंधक	हैक्टर बेवेरेजिस प्रा.लि.	बी–82, साउथ सिटी 1 (एचओ), प्लाट नं.0 132, सैक्टर–3, मानेसर, गुड़गांव	रेडी टू सर्व फल पेय, एनर्जी ड्रिंक (पेपर बोट, टिजिंगा, दूध के परंपरागत पेय)	8588865819	hardeep@hactobeverages.com
7.	श्री विपिन मल्होत्रा,	सीईओ	कैगफार्म प्राइवेट लिमिटेड	एनएच–8, दिल्ली जयपुर मार्ग, खांडसा, गुरूग्राम, हरियाणा–122001	दोहरे उद्देश्य के ग्राम विशिष्ट पक्षी – चिकन– कुरोइलर, अंडे और मांस दोनों के लिए भारत के 19 राज्यों तथा अफ्रीका व म्यांमार सहित 7 देशों में बिक्री	9818577733	vipin.kegg@gmail.com
8.	श्री राजीव गुलाटी	निदेशक	महेशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड (एमडीएच मसाले)	139 उद्योग विहार, फेज–1, गुड़गांव (हरियाणा)	मसालों का प्रसंस्करण	99101740044	Export@mdspices.in
9.	श्री अमित कलकल	कंटेंट मैनेजर	एग्री बिजनेस एकेडमी	एग्री बिजनेस अकेडमी, शिवाजी स्टेडियम, मैट्रो स्टेशन, आरक्यूब स्यूट, संख्या 06 और 07, लोअर ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली–110001	खाद्य एवं कृषि, प्रशिक्षण कस्टमाइज़्ड कंटेंट	9717012984	amit@agribusiness@acadmic
10.	श्री मनीष मानसिंगका	प्रबंध निदेशक	श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	72, कल्पतरू स्क्वायर, कांधीविता लेन, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी, पूर्व मुम्बई	वेयरहाउस सेवा प्रदानकर्ता	9810021850	maheshmansigka@kalptaru.com
11.	श्री आशीष वर्मा	एनसीआर बिजनेस मैनेजर	फ्यूचर ग्रुप (बिग बाजार)	शहर माल, एमजी रोड, गुड़गांव, हरियाणा	किराना	7428188001	ashish.verma@futureretail.in

12.	श्री विनीत पसरीचा	डीजीएम – वित्त	रिलायंस रिटेल लिमिटैड	आर.के. 4 स्क्वायर, बिल्डिंग सं.4, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज–2, गुड़गांव	फुटकर विक्रेता	9958101286	vineet.pasricha@gmail.com
13.	श्री राजन अग्रवाल	सीईओ	अमृत फीड्स	सैक्टर–110, नया पालम विहार, गुरूग्राम 122017	सभी प्रकार के पशु आहारों जैसे कैटल फीड, रेबिट फीड आदि के निर्माता	9810146240	Amritfeeds@gmail.com
14	श्री गौरव तिवारी	सह–संस्थापक	पियानो	सैक्टर–78, 1817, नोएडा, भारत, इसके अतिरिक्त डेलावयर (यूएसए) और लंदन (यू.के.) में भी	सेंसर आधारित ऐसी प्रणाली जो किसानों को वास्तविक समय के मृदा एवं पर्यावरणीय कारकों की सूचना प्रदान करती है	956860666	gaurav@pyeno.co.uk
15.	श्री अमित अग्रवाल	प्रबंध निदेशक	हल्दी राम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	ब 1/एच8, हल्दीराम, मोहन एस्टेट, दिल्ली	रेस्त्रा एवं मिटाई का व्यापार	9811558970	Sanjeev.yadav@haldiram.com
16	श्री सुकम सेतिया	निदेशक	चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड	कैथल रोड, करनाल	बासमती चावल	9811616255	Sales@setiaoverseas.com
17	श्री तरसेम राजीवाल	मालिक	आर.डी. ट्रेडर्स	अगरोहा मार्ग, बरवाला जिला, हिसार (हरियाणा)	कपास मिल, ओटाई, तेल मिल, खली, बिनौला	94160433608	Rdtraders5454@gmail.com
18.	श्री तरसेम बंसल	निदेशक	गंगा कॉटन एंड एलाइड इंडिया लिमिटेड, सिरसा	समशाबाद पट्टी, सिरसा, हरियाणा	कपास मिल, ओटाई मिल और खली	9215700098	Gangacotton@gmail.com
19.	श्री सुशील मित्तल	मालिक	आदित्य एग्रो इंडिया, सिरसा, हरियाणा	इंडस्ट्रियल एरिया, सिरसा, हरियाणा	कपास मिल, ओटाई मिल और खली	9215049853	Adityaagrocirsa@gmail.com
20..	श्री श्याम सुंदर	निदेशक	लिंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	टोहाना मार्ग, भुना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा)	कपास मिल, ओटाई मिल और खली	9729246006	lilbhuna@rediffmail.com

हरियाणा सरकार की पहल

– किसानों से सीधा संवाद

सांस्कृतिक
गतिविधियां

2nd AGRI LEADERSHIP
SUMMIT-2017
ASSOCHAM

2nd AGRI

2nd AGRI
18-20 March, 2017

सम्मेलन समाचार

सूरजकुंड में दूसरे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का समापन

किसान के एक-एक दाने का ऑनलाइन रखा जाएगा हिसाब-किताब : मुख्यमंत्री

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की फसल की बुआई से लेकर बिक्री तक के लिए फुडनेट नामक एक ऑनलाइन योजना को लागू करेगी। इसके तहत किसान की फसल की बुआई, कटाई, उठान, पैकिंग और बिक्री तक की जानकारी फिफो साफ्टवेयर के तहत दर्ज की जाएगी। ताकि यह पता रहे कि किस किसान ने किस भूमि पर क्या फसल उगाई। उसका क्या स्टेटस है।

मुख्यमंत्री द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान द्वारा उगाया गए एक-एक दाने का हिसाब किताब ऑनलाइन रखा जाएगा। ताकि किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बारे में विभिन्न प्रदेशों की योजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही यह ... जाएगी।

मीडिया से बात करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल साथ में बैठे कृषि मंत्री ओपी धनखड़।

कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के किसान धान व गेहूं जैसी परंपरागत खेती कर रहे हैं। अगर वे अपने गांव के नजदीकी शहर की जरूरत को ध्यान में रखकर खेती करें तो किसान खुशहाल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार योजना बना रही है कि जिस प्रकार से ... प्रति वर्ष ...

कृषि उत्पादों व किसानों को जानकारी देने के लिए मेला लगाया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड परिसर का उपयोग मेल कैलेंडर के तौर किया जा सकता है। यहां कुक फेयर, ट्रेड फेयर इत्यादि आयोजित किए जा सकते ...

10 हजार ही बचत करता है किसान, इस खाई को पाटना होगा : राज्यपाल

हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा है कि भारत तभी उन्नति करेगा, जब किसान की उन्नति होगी। देश में 60 फीसदी आबादी किसान वर्ग से है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि साल भर पूरे परिवार के साथ खेत में परिश्रम कर हर वर्ग की जरूरत को पूरा करने वाला किसान महज 10 हजार रुपए ही बचत कर पाता लेकिन पूंजीपति वर्ग अपनी धनबल शक्ति के कारण एक ही साल में लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाता है। आर्थिक ...

समापन समारोह | कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समापन समारोह पर राज्यपाल सोलंकी की खरी-खरी

किसानों और पूंजीपतियों के बीच बढ़ रही आर्थिक खाई पाटनी होगी तभी देश उन्नति करेगा : राज्यपाल

- कप्तान बोले- भारत में 60 प्रतिशत किसान आबादी है, इसीलिए किसानों के लिए बन रहीं अब बड़ी योजनाएं

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

फरीदाबाद। किसान को सम्मानित करते प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी।

सफीदों के विधायक और किसान जसबीर को मिला पोल्ट्री रतन पुरस्कार

किसान द्वारा उगाए गए एक-एक दाने का हिसाब रखा जाएगा ऑनलाइन : मुख्यमंत्री

खेती करने की नई तकनीक को जानकर किसान हुए उत्साहित

मेले में किसानों ने एक दूसरे के अनुभव किए शेयर

किसान से बातचीत

कुशल प्रबंधन के बूते बीज, नर्सरी और प्याज को लाभ

15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच करें ट्रांसप्लांट

पानी कब-कब दें

किसान एग्रो लीडरशिप 18 से 20 मार्च तक, किसान नेता दूसरे किसानों को प्रेरित करेंगे

10 रुपए किलो आलू खरीद 20 में नहीं बिकेगा चिप्स का पैकेट, किसान खुद तैयार करेंगे व बेचेंगे चिप्स : धनखड़

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों से 10 रुपए किलो आलू खरीदकर 100 ग्राम चिप्स का पैकेट 20 रुपए में बेचने वालों पर बड़ी लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। यदि चिप्स का पैकेट बाजार में बिकेगा तो वह खुद किसान बनाएगा और बेचेगा। एनसीआर के 50 किलोमीटर के दायरे में हम ऐसी खेती करेंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी की जरूरत की सभी खाद्य वस्तुएं मिल सकें। इसके लिए हम दिल्ली एनसीआर बोर्ड से आर्थिक मदद लेंगे। धनखड़ मंगलवार को सूरजकुंड के राजहंस होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने सूरजकुंड पर्यटन स्थल में आयोजित होने वाले देश के दूसरे कृषि नेतृत्व शिखर (एग्री लीडरशिप समिट) कार्यक्रम के बारे ...

फरीदाबाद | पत्रकारों से बातचीत करते कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़।

कि बड़ा कार्यक्रम 18 मार्च से शुरू होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 20 मार्च को इसका समापन हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि एग्री लीडरशिप में एक लाख से अधिक किसानों को पहुंचना है। तीन दिवसीय यह कार्यक्रम हमारे लीडर्स किसानों के जरिए दूसरे किसानों को प्रेरित करेंगे, उन्हें दिशा दिखाएंगे, ताकि वे उन्नत किसान बन सकें। इसमें अंतर्राष्ट्रीय किसान, राष्ट्रीय स्तर ... और उपलब्धि ...

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

एक हजार गावों से शुरू होगा गो नस्ल सुधार केंद्र

एग्री समिट में लेंगे हिस्सा

न्यू इंडिया बनाने के लिए किसानों को बढ़ाना होगा आगे: राज्यपाल

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समापन पर पहुंचे राज्यपाल सोलंकी

इन्हें मिला पुरस्कार

'अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुसार करनी होगी खेती'

धनखड़ जी, इन मेलों से नहीं होगी किसान की तरक्की: बीरेंद्र सिंह

40 लाख को रोजगार की जरूरत, 4 लाख नौकरियां

बागवानी को दिलाई जाएगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: धनखड़

तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक फार्म ट्रेडिंग पर हुआ मंथन

अंतिम दिन लिंक्स मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फार्म ट्रेडिंग पर चर्चा हुई

द्वितीय कृषि शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन

हमें दिल्ली के सालाना 36 हजार रु. करोड़ के कारोबार को हथियाना होगा : ओपी धनखड़

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने सूरजकुंड में द्वितीय कृषि शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जोर देकर कहा कि हमें हर हालत में दिल्ली के रोजाना के 100 करोड़ रु. के कारोबार को हथियाना होगा। ... हम अपने मकसद में 100 ... भी सफल हुए तो हरियाणा को ... 36 हजार करोड़ और 50 ... सफलता मिली तो 18 हजार ... रुपए प्राप्त कर सकेंगे। इसके ... हरियाणा की जीडीपी को ... उछाल मिलेगी। लेकिन ... संभव हो सकेगा, जब हम ... रहने वाले 4 करोड़ लोगों ... के हिसाब से परंपरागत ... को बदलेंगे।

... सरकार ने यह फैसला ... अब किसानों को एक ... क पुरस्कार राशि दी ... स्कार की शुरुआत ... से की जा रही है। ... यह फैसला सम्मेलन ... ही ले लिया गया ... गीय अधिकारियों ... णा करके उन ... को, जिन्हें हम ... का नाम दे रहे ...

फरीदाबाद. सूरज कुंड में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़।

उत्पादन विशेषता पर एक लाख का रतन पुरस्कार

कृषि मंत्री ने कहा कि पैरी अर्बन खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश स्तर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य रतन पुरस्कार, फल उत्पादन के क्षेत्र में फल रतन पुरस्कार, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में सब्जी रतन पुरस्कार, फूल उत्पादन के क्षेत्र में फूल रतन पुरस्कार और जैविक खेती के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान को हरियाणा जैविक रतन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इन प्रगतिशील किसानों को एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

53 किसानों को किया पुरस्कृत

शिखर सम्मेलन में रविवार को राज्य के कुल 53 किसानों को पुरस्कृत किया गया। इनमें 6 पुरस्कार राज्य स्तर, पुरस्कार जिला स्तरीय बागवानी क्षेत्र के किसानों को दिया गया। इसके अतिरिक्त 21 पुरस्कार मत्स्य पालन के लिए जिला स्तर पर दिया गया।

इन किसानों को मिले पुरस्कार

अंबाला के बिशनपाल सिंह राणा को फल रतन, रोहतक के शिलकराम धनखड़ को सब्जी रतन पुरस्कार, कैथल के राजेश खेरी को जैविक रतन पुरस्कार, झज्जर की सिवानी मलेश्वरी को फूल रतन पुरस्कार व झज्जर के डावला गांव के जयपाल को मत्स्य रतन पुरस्कार दिए गए। एक-एक लाख रुपए की राशि भी दी गई। इसके अलावा नीलोखेड़ी करनाल के सुल्तान को मछली पालन के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए की राशि दी गई। ये पुरस्कार विधानसभा ...क्ष कंवरपाल और ... कैप्टन अभिमन्यु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ ने दिए।

'युवराज' के सामने नेताओं का आकर्षण पड़ा फीका

फरीदाबाद (ब्यूरो)। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में दूसरी बार आए 9 करोड़ के भैंसे युवराज के सामने नेताओं का आकर्षण भी फीका पड़ गया है। युवराज को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। कुरुक्षेत्र से आए युवराज के मालिक का दावा है कि युवराज की कीमत 9 करोड़ लगाई गई। इसे देखने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े थे। सूरजकुंड की वादियों में चल रहे तीन दिवसीय द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में प्रदेश के किसान अपने-अपने पशु लेकर पहुंच रहे हैं। शनिवार को जब दर्शकों को युवराज के आने की सूचना मिली तो उसे देखने चल पड़े। दस साल का युवराज नौ बार देश के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनियों में चैंपियन घोषित किया जा चुका है। मुर्राह नस्ल का युवराज ही नहीं युवराज की मां गंगा (भैंस) भी सबसे अलग है। वह भी साढ़े 26 लीटर दूध देकर एक रिकॉर्ड बना चुकी है।

ये है युवराज की खुराक

कर्मवीर ने बताया कि युवराज रोजाना 20 लीटर दूध चार किलो सेब, चार किलो दाना खाता है। ... किसी भी ... से कम नहीं है। उसकी सेहत के लिए उसे डेढ़ घंटे तक रोजाना सैर कराई जाती है। उसकी खुराक व देखरेख में रोजाना 2500 रुपए खर्च किए जाते हैं। उसका पिता योगराज भी कई बार राष्ट्रीय चैंपियन रहा है।

ऐसे रखा नाम : मुर्राह नस्ल के झोटे का नाम युवराज मालिक कर्मवीर ऐसे ही नहीं रखा गया था। उन्होंने बताया कि 2007 में जब क्रिकेटर युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। उसी दौरान इसका जन्म हुआ था। युवराज के इस कारनामे पर ही इस भैंसे का नाम युवराज रखा गया था।

मुर्राह नस्ल की भैंस की कीमत एक करोड़

फरीदाबाद। हांसी हिसार से मास्टर होशियार सिंह अपनी मुर्राह नस्ल की भैंस धन्नो रानी को सूरजकुंड में लेकर पहुंचे। जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। कोई सेल्फी लेना चाहता था कोई उसकी कीमत पूछ रहा था। धन्नो रानी की कीमत एक करोड़ रुपये है। जिसको आंध्र के पशुपालक ... खरीदना चाहा ...

दूध उत्पादन में हरियाणा बनेगा नंबर वन : ओमप्रकाश धनखड़

मंत्री ने किया ऐलान, जो किसान समय पर ऋण चुकाएगा उसका सारा ब्याज विभाग देगा

अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद।

किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील

दो लाख गांवों में दूध संग्रहण

देशी गाय का घी खाकर महिलाएं

पशुधन दोगुना करने का लक्ष्य

आयोजक :

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HARYANA
KRISHI BHAWAN, SECTOR 21, PANCHKULA, HARYANA.
CALL: 0172 2570662,
FAX: 0172 2563242
email: agriharyana2009@gmail.com

DIRECTORATE OF HORTICULTURE HARYANA
UDHYAN BHAWAN, SECTOR 21, PANCHKULA, HARYANA.
CALL: 0172 2582322, 2582590
FAX: 0172 2585595
email: hortharyana@gmail.com

HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION
Bays 15-18, Sector 2, Panchkula
CALL: 0172-2578829-31
FAX: 0172-2578481
email: hwc@hry.nic.in

HARYANA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Bays No. 15-20, Sector -4, Panchkula, Haryana
CALL: 0172-2561305, 2561324
FAX: 0172-2561310, 2561326
email: haicpkl@gmail.com

HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
Beej Bhawan, Bays No. 3-6, Sector 2, Panchkula, Haryana 134115
CALL: 0172-257 7582, 2577755
FAX: 0172-2577583
email: mdhsdcl@gmail.com

HARYANA LAND RECLAMATION & DEVELOPMENT CORPORATION
HLRDC,Bays No.1-2, Sector-4,Panchkula
CALL: 0172-2568936

HARYANA STATE SEED CERTIFICATION AGENCY
Bays 11-12, Sector-14, Panchkula
CALL: 0172-2567642
FAX: 0172-2574134
email: hsscapkl@gmail.com

HARYANA KISAN AYOG
Head Office: Anaj Mandi, Sector-20, Panchkula-134116
CALL: 0172-2551664
FAX : 172-2551864
chairman@haryanakisanayog.org

DEPARTMENT OF CO-OPERATION HARYANA
Bays No. 27-30, Sector-2, Panchkula-134109.
CALL: 0172-2585023, 2583438
FAX: 0172-2585261
email: cooperatives@hry.nic.in

THE HARYANA STATE CO-OP APEX BANK LTD.
SCO 78-80, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh.
CALL: 0172-2704349, 2703198
email: harcobank@yahoo.com

HARYANA STATE FEDERATION OF COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD
Bays No.49-52, Sector-2, Panchkula
CALL: 0172-2590821-822
FAX: 0172-2590701
email: haryanasugarfed@gmail.com

HARYANA DAIRY DEVELOPMENT CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
Bay Nos. 21-22, Sector-2, Sahkarita Bhawan, Panchkula. Haryana, India
CALL: 0172-2585513, 2586487, 2587507
FAX: 0172-2587527
email: hddcfl@hry.nic.in

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT HARYANA
Pashudhan Bhawan
Bays No. 9-12 Sector-2 Panchkula, Haryana
CALL: 0172-2574662, FAX: 0172-2586837
email: pashudhanhar@rediffmail.com

HARYANA STATE LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD
Pashudhan Bhawan
Bays No. 9-12 Sector-2
Panchkula, Haryana (INDIA)
CALL: 0172-2574662, FAX: 0172-2586837
email: pashudhanhar@rediffmail.com

Fish for Health
Fish for Wealth

FISHERIES DEPARTMENT HARYANA
SCO - 6, Sector - 16, Panchkula, Haryana
CALL: 0172-2565743, 2566081, 2565961
email: fisheries.haryana@gmail.com

DEPARTMENT OF INFORMATION PUBLIC RELATION & LANGUAGES AND ART & CULTURAL AFFAIRS
SCO 200-201, Sector 17-C, Chandigarh
CALL: 0172-5059100
email: dgiprharyana@yahoo.com

NODAL AGENCY :

HARYANA STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD

C-6, Sector - 6, Panchkula (Haryana)
Call : 0172 - 2560883, 2560193
Fax : 0172 - 2560197
E-mail : ca.mandiboard@gmail.com
paca.mandiboard@gmail.com

CCS HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY

Hisar - 125 004, India
Call : +91-1662-231640, 284301
Fax : +91-1662-234952
E-mail: vc@hau.ernet.in

hafed

THE HARYANA STATE COOPERATIVE SUPPLY AND MKT. FED. LTD.

Sector - 5, Panchkula, Haryana
Call : 0172-2590518, 2590709
E-mail : hfdmd@hry.nic.in, hafed@hry.nic.in

सह-आयोजक :

MINISTRY OF AGRICULTURE GOVT. OF INDIA

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURE RESEARCH (ICAR)

SFAC लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
SMALL FARMER AGRI BUSINESS CONSORTIUM (SFAC)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NATIONAL HORTICULTURE BOARD
NATIONAL HORTICULTURE BOARD (NHB)

बागवानी मिशन Horticulture Mission
MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE (MIDH)

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

National Food Security Mission
Ministry of Agriculture
Government of India

एन एससी NSC
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (NSC)

MOFPI
Ministry of Food Processing Industries
Government of India

CH. CHARAN SINGH HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY HISAR (CCSHAU)

LALA LAJPATRAI UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES HISAR (LUVAS)

NABARD

NCCF
NATIONAL CO-OPERATIVE CONSUMERS FEDERATION OF INDIA

एपीडा APEDA

KRIBHCO

NAFED
A Farmers' Cooperative

IFFCO

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

NCCD

Department of AYUSH
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

NDRI

INDIAN POTASH LIMITED
IPL

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एन.एफ.एल. NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

NDDB
National Dairy Development Board

HAREDA
DEPARTMENT OF RENEWABLE ENERGY HARYANA

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT HARYANA

IRRIGATION DEPARTMENT HARYANA

सेल SAIL
Steel Authority of India Limited.

DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, HARYANA

INDUSTRY DEPARTMENT HARYANA

आयोजक समिति

द्वितीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2017

हरियाणा किसान आयोग

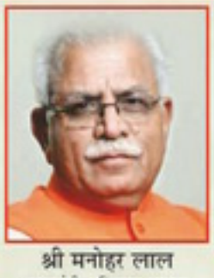

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

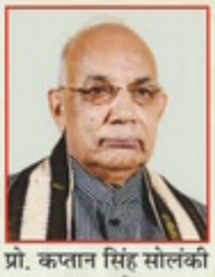

वि॰ सं॰ 2074 वर्ष 2017–18

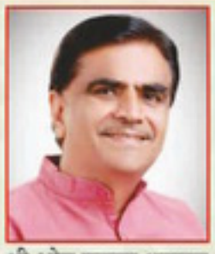

श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार

प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी
राज्यपाल, हरियाणा

श्री ओम प्रकाश धनखड़
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

चैत्र — वि॰सं॰ 2074 मार्च-अप्रैल - 2017 — वैशाख

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
मार्च नवसंवत् 2074	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

वैशाख — वि॰सं॰ 2074 मई - 2017 — ज्येष्ठ

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ज्येष्ठ — वि॰सं॰ 2074 जून - 2017 — आषाढ़

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

आषाढ़ — वि॰सं॰ 2074 जुलाई - 2017 — श्रावण

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

श्रावण — वि॰सं॰ 2074 अगस्त - 2017 — भाद्रपद

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

भाद्रपद — वि॰सं॰ 2074 सितम्बर - 2017 — आश्विन

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

आश्विन — वि॰सं॰ 2074 अक्तूबर - 2017 — कार्तिक

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

कार्तिक — वि॰सं॰ 2074 नवम्बर - 2017 — मार्गशीर्ष

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

मार्गशीर्ष — वि॰सं॰ 2074 दिसम्बर - 2017 — पौष

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

पौष — वि॰सं॰ 2074 जनवरी - 2018 — माघ

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

माघ — वि॰सं॰ 2074 फरवरी - 2018 — फाल्गुन

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

फाल्गुन — वि॰सं॰ 2074–75 मार्च - 2018 — चैत्र

सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

अवकाश

04 अप्रैल	रामनवमी
09 अप्रैल	महावीर जयंती
13 अप्रैल	बैसाखी
14 अप्रैल	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती
28 अप्रैल	भगवान परशुराम जयन्ती
10 मई	बुद्ध पूर्णिमा
28 मई	महाराणा प्रताप जयंती
09 जून	संत कबीर जयन्ती
26 जून	ईद-उल-फितर
26 जुलाई	हरियाली तीज
15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी
02 सितम्बर	ईद-उल-जुहा (बकरीद)
21 सितम्बर	महाराजा अग्रसेन जयन्ती
23 सितम्बर	हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस
30 सितम्बर	दशहरा
01 अक्तूबर	मुहर्रम
02 अक्तूबर	महात्मा गांधी जयन्ती
05 अक्तूबर	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती
08 अक्तूबर	करवा चौथ
19 अक्तूबर	दीपावली
20 अक्तूबर	विश्वकर्मा दिवस
01 नवम्बर	हरियाणा दिवस
04 नवम्बर	गुरु नानकदेव जयन्ती
02 दिसम्बर	मिलाद-उल-नबी/ईद-ए-मिलाद
25 दिसम्बर	क्रिसमस दिवस
25 दिसम्बर	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती
26 दिसम्बर	शहीद उधम सिंह जन्मदिवस
14 जनवरी	मकर संक्रांति
22 जनवरी	बसंत पंचमी
24 जनवरी	सर छोटू राम जयन्ती
26 जनवरी	गणतंत्र दिवस
10 फरवरी	महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
13 फरवरी	महाशिवरात्रि
1 मार्च	गुरु रविदास जयन्ती
2 मार्च	होली
23 मार्च	शहीदी दिवस
29 मार्च	महावीर जयन्ती

अनाज मण्डी, सैक्टर–20, पंचकूला (हरियाणा)
दूरभाष : 0172–2551664 (कार्यालय)
Website : www.haryanakisanayog.org

हरियाणा किसान आयोग, अनाज मण्डी, सेक्टर 20, पंचकूला, हरियाणा • वेबसाइट : www.haryanakisanayog.org